● वर्ष-3
● अंक-198
रायपुर, रविवार
31 मार्च 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

samacharpacheesa@gmail.com

पेज-6›› क्रू को दो फिल्मों ने दी ओपनिंग के....

भाजपा घोषणापत्र समिति का ऐलान, राजनाथ सिंह अध्यक्ष

27 सदस्यों की होगी समिति, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साय भी शामिल

नई दिल्ली/रायपुर। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है. इसी कड़ी में बीजेपी ने चुनावी घोषणापत्र के लिए कमेटी का गठन किया है. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनाव घोषणापत्र समिति की घोषणा करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को समिति का अध्यक्ष बनाया है. राजनाथ सिंह के अलावा कमेटी में 27 सदस्य होंगे. वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कमेटी का संयोजक बनाया गया है. बीजेपी महासचिव अरुण सिंह की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस समिति के गठन को मंजूरी दी है. समिति में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी और राजीव चंद्रशेखर के अलावा

पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और कुछ पूर्व उपमुख्यमंत्री भी शामिल हैं. घोषणा पत्र समिति में कई राज्यों के सीएम और पूर्व सीएम को जगह दी गई है. मुख्यमंत्रियों में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, असम के सीएम हिमंत विश्व शर्मा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नाम हैं। जबकि पूर्व मुख्यमंत्रियों में शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे के नाम शामिल हैं. वहीं, समिति के अन्य सदस्यों में पूर्व केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद, पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, राधामोहन दास अग्रवाल, राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा शामिल हैं.

इसके अलावा कमेटी में पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा, किरेन रिजिजू, अश्विनी वैष्णव, हिमंता बिस्वा सरमा, वसुंधरा राजे, स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, विष्णुदेव साय, शिवराज सिंह चौहान, रवि शंकर प्रसाद, सुशील मोदी,अनिल एंटनी, केशव प्रसाद मौर्य, राजीव चंद्रशेखर, विनोद तावड़े, राधामोहन दास, ओपी धनखड़, तारीक मंसूर समेत कई और नेताओं को शामिल किया गया है. गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी अब तक उम्मीदवारों की सात लिस्ट जारी कर चुकी है. बीजेपी ने 407 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है. गौरतलब है कि बीजेपी बीते महीने से ही लोकसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी. पार्टी ने लोगों से सुझाव मांगने के लिए अलग-अलग इलाकों में रथ भी रवाना किए थे.

मुख्यमंत्री साय ने की बूथ विजय संकल्प अभियान की शुरुआत

बूथ विजय संकल्प अभियान में कार्यकर्ता जुट जाएँः साय

भाजपा कार्यकर्ता हर बूथ तक पहुँचकर शानदार जीत का इतिहास रचे, लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के झूठे वादों पर जनता कतई ऐतबार नहीं करेगी

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के बूथ विजय संकल्प अभियान की शुरुआत करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और भाजपा कार्यकर्ताओं के सामने हर बूथ में 370 वोटों की बढ़त हासिल करके भाजपा के बूथ विजय संकल्प अभियान को सफल करने का गुरुतर दायित्व है। श्री साय ने आह्वान किया कि भाजपा के नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता हर बूथ तक पहुँचकर भाजपा की शानदार जीत का इतिहास रचकर बूथ विजय संकल्प अभियान में पूरे मनोयोग के साथ जुट जाएँ। श्री साय रायपुर ग्रामीण मंडल के ग्राम कांदुल में आयोजित बूथ विजय संकल्प अभियान के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज पूरे छत्तीसगढ़ में बूथ विजय संकल्प अभियान का शुभारंभ हो रहा है। इस अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में तीन चरणों में संपन्न होना है। हमें कांग्रेस प्रत्याशियों की जमानत जब्त कराने और श्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लक्ष्य के साथ हर बूथ में भाजपा को रिकॉर्ड बढ़त के साथ जिताने का संकल्प लेकर चुनावी रण में जाना है। श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी सबके विकास के लिए, गाँव-गरीब, किसान, युवा, महिला, सबके उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। भाजपा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास के मूलमंत्र के साथ कार्य कर रही है। कांग्रेस और उसकी पिछली प्रदेश सरकार पर जनता के साथ धोखाधड़ी और छलावा करने का आरोप लगाते हुए श्री साय ने कहा कि हर लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशियों की जमानत जब्त कराना है क्योंकि कांग्रेसी झूठे हैं। सन 2018 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता से झूठे वादे करके कांग्रेस ने प्रदेश में सरकार बनाई लेकिन प्रदेश की जनता से किए 36 वादों में से एक भी वादे को पूरा नहीं किया। कांग्रेस के झूठे वादों पर पिछले विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता ने रत्तीभर भरोसा नहीं किया और अब आने वाले चुनाव में भी कांग्रेस के झूठे वादों पर जनता कतई ऐतबार नहीं करेगी।

प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आगामी 7 मई को रायपुर लोकसभा के लिए मतदान होना है और सभी कार्यकर्ताओं की यह महती जिम्मेदारी है कि शत-प्रतिशत मतदान कराके इस चुनाव में कमल के निशान पर बटन दबाकर भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल को जिताना है और केंद्र में प्रधानमंत्री श्री मोदी की सशक्त सरकार तीसरी बार बनानी है। रायपुर से भाजपा ने एक ऐसा प्रत्याशी उतारा है जो सबके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। श्री अग्रवाल लगातार कार्यकर्ताओं के हर सुख-दुःख में जनता के सभी कार्यों में शामिल होते हैं। तीन माह के अत्यल्प कार्यकाल में ही मोदी की गारंटी के अधिकांश वादों पर हुए काम और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों की चर्चा भी मुख्यमंत्री श्री साय ने की और कहा कि भाजपा ने अपने मोदी की गारंटी को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है।

भाजपा की आठवीं सूची जारी सनी देओल का टिकट कटा

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की आठवीं सूची जारी कर दी है। सूची में ओडिशा की तीन, पंजाब की छह और पश्चिम बंगाल की दो लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का एलान किया गया है। इसमें बड़ी खबर यह है कि पंजाब की गुरदासपुर लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद और बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल का टिकट काट दिया गया है। उनकी जगह दिनेश सिंह को टिकट दिया गया है। इसके अलावा दूसरे दलों से आए सांसदों को भी टिकट दिया गया है। भाजपा ने शनिवार को जिन 11 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की, उसमें भर्तृहरि महताब, रवनीत सिंह बिट्टू, सुशील कुमार रिंकू और परनीत कौर जैसे कई नेताओं के नाम हैं। ये सभी हाल ही में अलग-अलग दलों से भाजपा में शामिल हुए थे। सभी को उन सीटों से ही चुनावी मैदान में उतारा गया है, जिनका वे मौजूदा लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं।

कांग्रेस नेता शिवराज की बहू भाजपा में शामिल

मुंबई। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल की बहू अर्चना पाटिल चाकुरकर शनिवार को महाराष्ट्र में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस और अन्य पार्टी नेताओं की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हो गईं। मुंबई में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, देवेंद्र फड़नवीस ने कहा कि अर्चना पाटिल चाकुरकर के शामिल होने से लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में भाजपा मजबूत होगी। फडणवीस ने कहा कि यह हमारे लिए खुशी की बात है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, लोकसभा अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री रहे शिवराज

पाटिल के परिवार से कोई हमारी पार्टी में शामिल हो रहा है। यह बहुत बड़ी बात है। चाकुरकर ने फडणवीस से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की। वह उदगीर में लाइफकेयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की चेयरपर्सन हैं और उनके पति शैलेश पाटिल चंदुरकर कांग्रेस के राज्य सचिव हैं। अर्चना के ससुर, शिवराज पाटिल ने 10 जुलाई, 1991 से 22 मई, 1996 तक लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 2004 और 2008 के बीच, उन्होंने पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन के तहत यूपीए सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया। पाटिल 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले के दौरान भी केंद्रीय गृह मंत्री थे, जिसमें कम से कम 192 लोगों की जान चली गई थी। हमलों के बाद हुई आलोचना के बाद उन्होंने 30 नवंबर 2008 को पद से इस्तीफा दे दिया।

महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव पांच चरणों में होंगे. मतदान 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई और 20 मई को होंगे। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। गौरतलब है कि देश में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें महाराष्ट्र में हैं।. . . महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 23 सीटें जीती थीं, जबकि शिवसेना ने 18 सीटें हासिल की थीं।

एक और शादी करना चाहते हैं बदरुद्दीन! हिमंता बोले-

अभी कर लें, बाद में जाना पड़ेगा जेल

नई दिल्ली। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल को उनकी वैवाहिक योजनाओं को लेकर कड़ी चेतावनी जारी की। सरमा ने कहा कि यदि अजमल दोबारा शादी करने का इरादा रखते है, तो उन्हें आगामी चुनावों से पहले ऐसा करना चाहिए। सरमा ने आगे कहा कि चुनाव से पहले अजमल की शादी में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित होगी, क्योंकि यह मौजूदा कानूनों के तहत वैध है। हालाँकि, चुनाव के बाद समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के लागू होने से परिदृश्य बदल जाएगा। हिमंत बिस्वा सरमा ने बदरुद्दीन अजमल को लेकर कहा कि उन्हें अभी शादी कर लेनी चाहिए, चुनाव के बाद यूसीसी असम आएगी, फिर गिरफ्तारी होगी। इसलिए अगर वह चुनाव से पहले शादी कर लें तो ठीक है। फिर हम उनकी शादी में भी जायेंगे। अब ये गैरकानूनी नहीं है। उन्होंने कहा कि जहां तक मुझे पता है, उनकी एक पत्नी है, आज वह दो या तीन शादियां कर सकते हैं लेकिन चुनाव के बाद हम बहुविवाह बंद कर देंगे।

प्रमुख समाचार

ईडी के रडार में 'आप' का एक और मंत्री, कैलाश से घंटों पूछताछ

नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ईडी के रडार में दिल्ली के एक और मंत्री आ गए हैं. परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत से ईडी ने शनिवार को करीब पांच घंटे तक पूछताछ की है. कैलाश गहलोत 2021-22 के लिए नई शराब नीति की तैयारी और कार्यान्वयन के लिए पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ मंत्रियों के समूह का हिस्सा थे. ईडी ने अपने आरोपपत्र में यह भी आरोप लगाया है कि गहलोत के पास एक ही सिम नंबर था लेकिन उनकी आईएमईआई (अंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान) तीन बार बदली गई. ईडी ने अपने आरोप पत्र में गहलोत के नाम का उल्लेख किया है और मामले में पहले गिरफ्तार किए गए आप संचार प्रभारी विजय नायर के संदर्भ में कहा है कि नायर गहलोत को आवंटित सरकारी बंगले में रहते थे. गहलोत दक्षिण पश्चिम दिल्ली के नजफगढ़ में रहते हैं.

केजरीवाल की पत्नी सुनीता से मिलीं कल्पना सोरेन

नई दिल्ली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद देश की सियासत गर्म है. इंडिया गठबंधन के लोग ईडी की इस कार्रवाई पर भाजपा पर निशाना साध रहे हैं. इस बीच झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से शनिवार को दिल्ली में मुलाकात की. मुलाकात के बाद कल्पना सोरेन ने मीडिया से बातचीत की. उन्होंने कहा कि झारखंड में दो माह पहले क्या था यह सबने देखा. यही चीज वर्तमान समय में दिल्ली में हो रहा है. अरविंद केजरीवाल को भी मेरे पति हेमंत सोरेन की तरह जेल में डाला गया.

हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकतेः गवई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश और कॉलेजियम में शामिल जस्टिस बीआर गवई ने शुक्रवार को कहा कि सरकार की नीतियों की समीक्षा करने में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में अगर कार्यपालिका अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहती है तो न्यायपालिका हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती है। जस्टिस गवई ने हार्वर्ड केनेडी स्कूल में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए ये बातें कही है। आपको बता दें कि हाल ही में सरकार की विवादास्पद चुनावी बांड योजना को रद्द करने वाली पांच जजों की संविधान पीठ में जस्टिस गवई भी शामिल थे। उन्होंने कहा देश के प्रत्येक अंग को अपने क्षेत्र में कार्य करने की शक्ति है। विधायिका कानून बनाती है। कार्यपालिका उन्हें लागू करने के साथ-साथ प्रशासन चलाती है। न्यायपालिका किसी कानून या संविधान के तहत मुद्दों को लागू करती है, व्याख्या करती है और निर्णय लेती है। उन्होंने कहा कि अदालतों को राज्य के विभिन्न अंगों यानी विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा और निगरानी करनी होती है।

ननद-भौजाई के बीच बारामती में होगा मुकाबला

मुंबई। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने शनिवार को सुनेत्रा पवार को चर्चीत बारामती लोकसभा सीट से उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा, जिससे यह पवार परिवार के भीतर सीधी लड़ाई बन गई। सुनेत्रा पवार अजित पवार की चचेरी बहन और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। यह घोषणा आज तीव्र अटकलों के बीच हुई, जिसमें राकांपा नेता सुनील तटकरे ने आधिकारिक तौर पर सुनेत्रा अजीत पवार को बारामती लोकसभा क्षेत्र के लिए उम्मीदवार घोषित किया। वहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी - शरद चंद्र पवार पार्टी की केंद्रीय संसदीय समिति ने आज लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा की। सूची की घोषणा करते हुए राज्य इकाई प्रमुख जयंत पाटिल ने कहा कि सुप्रिया सुले और अमोल कोल्हे को क्रमशः बारामती और शिरूर निर्वाचन क्षेत्रों से बरकरार रखा गया है पार्टी ने पांच सीटों - वर्धा, डिंडोरी, बारामती, शिरूर और अहमदनगर के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है।

भाजपा नेता के ठिकानों पर आईटी का छापा

दुर्ग। लोकसभा चुनाव के पहले दुर्ग में भाजपा नेता और बिल्डर्स के घर और दफ्तरों में आईटी की टीम ने दबिश दी है। भाजपा नेता के पुलगांव में स्थित अमर इंफ्रास्ट्रक्चर के ठिकानों पर आईटी की टीम ने छापामारा है जिसमे आईटी के अधिकारियों की टीम आठ गाड़ियों में 20 से ज्यादा अधिकारी पहुंचे हैं। छापेमारी में कई डिजिटल साक्ष्य के साथ-साथ अहम दस्तावेज भी मिले हैं आईटी की टीम पूछताछ कर रही है। भाजपा नेता अमर इंफ्रास्ट्रक्चर के संचालक हैं जो प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी सड़क, पुल एवं पुलिया सरकारी टेंडर्स का काम करता है। भाजपा नेता चतुर्भुज राठी के भाई अलग-अलग फर्म में काम करते हैं। वहीं भाजपा नेता चतुर्भुज राठी 2023 के विधानसभा चुनाव में दुर्ग शहर से भाजपा से टिकट की मांग की थी। लेकिन इस कार्रवाई से शहर में हड़कंप मचा हुआ है।

राजनेता अपने सहारे के लिए विदेशी तत्वों के सहयोग अथवा हस्तक्षेप की अपेक्षा करने लगे हैं?

खतरनाक है देश की राजनीति में विदेशी दखल

अभिरंजन कुमार

क्या भारत की राजनीति में विदेशी तत्वों का दखल बढ़ता जा रहा है या फिर भारत के राजनेता अपने सहारे के लिए विदेशी तत्वों के सहयोग अथवा हस्तक्षेप की अपेक्षा करने लगे हैं? भारत जैसे बड़े देश की राजनीति में विश्व के शक्तिशाली देशों की दिलचस्पी होना एक सामान्य बात लगती है, लेकिन यह सवाल इसलिए पैदा हुआ है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से एक ऐसा चलन देखने में आ रहा है, जो सामान्य से अलग है। इसमें हम यह देखते हैं कि विदेशी तत्वों की भारत में एक सहज-स्वाभाविक सामान्य सी दिलचस्पी तो है ही, लेकिन भारत के कुछ राजनीतिक लोग भी अपने फायदे के लिए विदेशों का मुंह देखने लगे हैं।

यद्यपि इस तरह के प्रयासों में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ के लोग शामिल हैं, लेकिन दोनों के उद्देश्य और तरीके स्पष्ट रूप से अलग हैं। जहां सत्ता पक्ष के लोग विदेशों में अपना प्रभाव दिखाकर देश में हवा बनाने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं, वहीं विपक्ष के लोग अपने बचाव, समर्थन और समस्याओं के समाधान के लिए दूसरे देशों मे भारत की सरकार के विरुद्ध माहौल बनाते हुए दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो हमने स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा कि दुनिया के अनेक महत्वपूर्ण देशों में जाकर उन्होंने भारतीय समुदाय की बड़ी-बड़ी रैलियां कीं और उसमें एक तरफ जहां भारत का गौरवगान किया, वहीं दूसरी तरफ भारतीय विपक्ष की प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से आलोचना भी की। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किये गए इस चलन में यह बात गौर करने की रही कि उन्होंने जब भी भारतीय विपक्ष की आलोचना की, भारतीय समुदायों के बीच ही की। विदेशी समुदायों के बीच भारतीय राजनीति पर बात करते हुए वे कभी नज़र नहीं आए।

दूसरी तरफ, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पिछले कुछ वर्षों के दौरान अमेरिका और ब्रिटेन जैसे महत्वपूर्ण देशों की अपनी यात्राओं का राजनीतिक इस्तेमाल किया है। इन यात्राओं के दौरान उन्होंने कई बार यह आरोप लगाया है कि भारत की सरकार यहां के लोकतांत्रिक ढांचे पर लगातार हमले कर रही है, साथ ही यहां प्रेस और न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी खतरे में है। लेकिन बात केवल कुछ भारतीय नेताओं के विदेशी धरती पर कुछ बयानों तक ही सीमित नहीं दिखाई देती, बल्कि भारत के कई आंतरिक मामलों में विपक्षी खेमे द्वारा तैयार किये गये नैरेटिव के आधार पर विदेशों से जिस तरह की आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वह चिंता का विषय हैं। सबसे पहले इस संदर्भ में भारत के हाल-फिलहाल के दो आंतरिक मामलों पर गौर करते हैं। एक - भारत में नागरिकता संशोधन कानून 2019 यानी सीएए का लागू होना, और दूसरा - शराब घोटाले के आरोप में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया जाना।

जहां तक सीएए का प्रश्न है, भारत का विपक्ष लगातार इसे धार्मिक रूप से भेदभाव करने वाला और मुसलमानों के खिलाफ बताता रहा है। इसी आधार पर 2019-20 में मुस्लिम समुदाय ने दिल्ली के शाहीन बाग समेत देश के अनेक हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी किये। ऐसी अफवाहें फैलाई गईं, जैसे कि इस कानून से भारत में बड़ी संख्या में मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी, जबकि सरकार द्वारा बार-बार स्पष्ट किया गया कि यह भारतीय नागरिकता देने का कानून है, न कि भारत के अल्पसंख्यकों की नागरिकता छीनने का कानून। इसके बावजूद भारतीय विपक्ष ने जिस तरह का नैरेटिव खड़ा किया, उसके कारण दुनिया भर में इस कानून को लेकर एक भ्रम का वातावरण दिखाई देता है। अमेरिका ने तो यहां तक कह दिया कि भारत में सीएए कानून लागू होने से हम चिंतित हैं और इस बात पर करीब से नज़र बनाए हुए हैं कि इस कानून को किस तरह से लागू किया जाता है। स्थिति ऐसी बनी कि भारत सरकार को जवाब में कहना पड़ा कि ऐसे बयान देने वालों को भारतीय परंपराओं और विभाजन के बाद भारत और नए बने देशों के इतिहास की जानकारी नहीं है।

इसके बाद दिल्ली में शराब घोटाले के आरोप में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी भारतीय विपक्ष ने जैसा नैरेटिव खड़ा किया, ठीक वैसे ही बयान जर्मनी और अमेरिका की तरफ से आ गए। दोनों देशों ने मामले पर नज़र होने की बात कही, साथ ही भारत को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया। हालात ऐसे बने कि भारत को इन दोनों देशों के राजनयिकों को तलब कर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी कि भारत में कानूनी प्रक्रियाएं एक स्वतंत्र न्यायपालिका पर आधारित हैं, उन पर कलंक या आक्षेप लगाने को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, भारत को यह भी कहना पड़ा कि कूटनीति में उम्मीद की जाती है कि विभिन्न देश एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल न दें और एक-दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करें।

बीजापुर में नक्सली बंद का असर बसों समेत वाहनों के थमे पहिए

बीजापुर। बस्तर में 30 मार्च को नक्सलियों ने बीजापुर बंद का आह्वान किया है।जिसका असर बीजापुर जिले में देखने को मिल रहा है। जिला मुख्यालय से लेकर भोपालपट्टनम, आवापल्ली, भैरमगढ़ तक व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे।यही नहीं इन इलाकों में यातायात व्यवस्था भी पूरी तरीके से ठप रही। आपको बता दें कि नक्सलियों ने 30 मार्च फर्जी मुठभेड़ के विरोध में बीजापुर बंद करने का आह्वान किया था। नक्सलियों के पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी के सचिव ने प्रेस नोट जारी किया था। नक्सलियों ने पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ करके ग्रामीणों की हत्या करने का आरोप लगाया गया था।

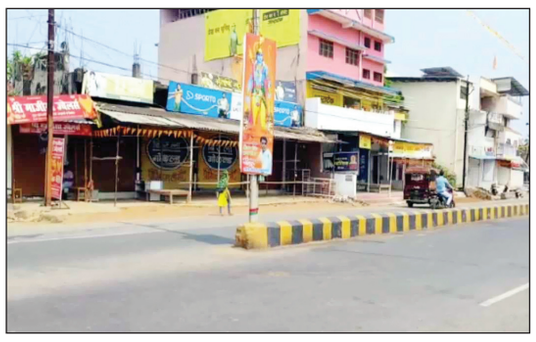

एंबुलेंस,हॉस्पिटल और परीक्षा देने वाले छात्रों को छूट

नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी करके बंद के दौरान अस्पताल, एंबुलेंस और परिक्षार्थियों को छूट दिया है।लेकिन परिवहन और व्यापारिक प्रतिष्ठान चलाने वाले व्यापारियों को नक्सलियों ने खुलेआम धमकी दी। नक्सलियों ने व्यापारियों समेत ट्रांसपोर्टर्स को चेताया कि यदि सेवाएं बंद नहीं कि तो इसकी जिम्मेदारी उनकी खुद की होगी।

जिला मुख्यालय में पूरी तरह से तालाबंदी

नक्सलियों की चेतावनी के बाद बीजापुर जिला मुख्यालय समेत जिले के चारों ब्लॉक के प्रतिष्ठान बंद हैं। वहीं चार ब्लॉक में आवागमन ठप है। सड़क सुनसान हैं। यात्री बस, ट्रक,ट्रैक्टर और छोटे वाहन भी नहीं दिख रहे। जगदलपुर से गीदम तक वाहनें चल रही हैं, दुकानें भी खुली हैं। लेकिन बीजापुर जिले में पूरे प्रतिष्ठान बंद हैं।वहीं बस स्टैंड में सन्नाटा पसरा पड़ा है।

क्यों नक्सलियों ने करवाया बंद

नक्सलियों का आरोप है कि जनवरी से लेकर अब तक 15 बेकसूर आदिवासियों की हत्या हुई। फर्जी मुठभेड़ करके पुलिस ने ग्रामीणों को नक्सली बता दिया।लिहाजा इसके विरोध में बंद बुलाया गया है। वहीं बंद को देखते हुए क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।जगदलपुर से सिर्फ एक डाक वाहन बीजापुर की ओर गया। डाक वाहन के ड्राइवर की माने तो जिले में एक भी वाहन नहीं दिखा। पुलिस ने भी अपने रणनीति के अनुसार सुरक्षा बल को तैनात करके रखा है। अक्सर बंद के दौरान सड़क जाम करने और पेड़ काटने की घटनाएं देखने को मिलती थी।लेकिन अब तक ऐसी किसी भी तरह की सूचना नहीं मिली है।वहीं यात्री बसों के पहिए पूरे तरह से ठप हैं।

पिरदा सहकारी समिति में हुए घोटाले मामले में तीन साल बाद दर्ज हुआ एफआईआर

- 4 करोड़ 44 लाख 65 हजार 510 रुपये का घोटाला
- नाम बताने से पुलिस कर रही हैं इंकार

महासमुंद। पिरदा सहकारी समिति में 2021 में किसानों से खरीदे धान, बारदाना के रखरखाव व भंडारण में 4 करोड़ 44 लाख 65 हजार 510 रुपए का घोटाला मामले में 7 लोगों पर न्यायालय के आदेश के बाद बसना पुलिस ने धारा 153, 3 के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। लेकिन किन-किन लोगों पर मामला दर्ज किया गया है, इसका उल्लेख न तो पुलिस ने डीएसआर में दिए हैं और न ही पुलिस का कोई जवान इन नामों को बता पाने में सक्षम हैं। आरोपियों के नाम को लेकर एसपी और थानेदार तक ने यहां तक कह दिया कि नाम नहीं बता सकते। इस समिति में खरीदी से 17 हजार 210 क्विंटल धान का स्टॉक कम मिला था। साथ ही धान की 65 हजार 467 बोरियां कम पाई गई थी।

इस मामले में अभी बसना पुलिस को संवेदनशील बताते हुए जिन आरोपियों के खिलाफ एफ आईआर दर्ज की गई है, उनके नाम बताने से इंकार कर रही है। हालांकि शिकायतकर्ता ने विभागीय जांच में जिन 7 लोगों पर अनियमितता का आरोप लगा था, उनका नाम सार्वजनिक कर दिया है। लेकिन इसकी पुष्टि करने में भी पुलिस परहेज कर रही है। इसके पहले भी शिकायतकर्ताओं के कहने पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया था। इसके बाद प्रार्थी न्यायालय की शरण में गए और न्यायालय से आदेश जारी होने पर पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई की है।

इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक आशुतोष सिंह ने बताया कि मामला साल 2020-21 में हुए धान घोटाले से संबंधित है। इसमें 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामले में वैधानिक कार्रवाई जारी है। नाम नहीं बता सकता।

वहीं बसना थाना प्रभारी शशांक पौराणिक ने कहा कि धान घोटाले मामले में 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर किया गया है। जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है, उनके नाम नहीं बता सकता। बस इतना ही ब्रीफ है कि धान घोटाले में कार्रवाई हुई है।

गौरतलब है कि पिरदा सहकारी समिति में 2021 में कुल 68539.20 क्विंटल धान खरीदी गई थी। जिसमें 17 हजार 210 क्विंटल धान की कमी पाई गई। तब राज्य सरकार 2500 रुपए के समर्थन मूल्य पर प्रति क्विंटल धान खरीद रही थी। लिहाजा धान खरीदी, रखरखाव और परिवहन में ही 4 करोड़ 30 लाख 26 हजार 800 रुपए की अनियमितता बरती गई। वहीं समिति में जांच के दौरान 65 हजार 467 बारदाने की कमी पाई गई। इस बारदाने की कीमत 14 लाख 38 हजार 710 रुपए है। यानी धान खरीदी और बारदाने में 4 करोड़ 44 लाख 65 हजार 510 रुपए का घपला किया गया है।

राजनांदगांव की जनता बघेल को ऐतिहासिक मतों से हराकर वापस पाटन भेजेगी: पांडेय

कवर्धा। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी व सांसद संतोष पाण्डेय ने पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल के ईवीएम वाले बयान पर पलटवार किया है। सांसद पांडेय ने भूपेश बघेल को खुली चुनौती दी है।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक सभा में अपने कार्यकर्ताओं से अपील की थी कि सभी लोकसभा सीटों पर 375 से ज्यादा कार्यकर्ता नामांकन जमा करें। ताकि अधिक संख्या में होने पर चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलैट पेपर से हो। इसी बयान पर सांसद संतोष पाण्डेय ने पलटवार करते हुए कहा है कि भूपेश बघेल जितनी संख्या में अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाना चाहते हैं लड़ा लें। लेकिन जीत तो केवल भाजपा की ही होगी। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल को खेलना नहीं आता तो पिच खराब करने की कोशिश में लगे हैं। इस तरह कार्यकर्ताओं को भड़काकर अपने ही खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ाना चाहते हैं। इससे साफ पता चलता है कि भूपेश बघेल डर गए हैं। इसलिए ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। बघेल मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में विधायक हैं। संविधान की शपथ लिए हैं। एक संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्ति द्वारा ऐसा बयान देना उनकी असली मानसिकता को प्रदर्शित करता है। बघेल ने अपने कार्यकाल में राजनांदगांव के साथ सौतेला व्यवहार किया था। जिसे जनता भूली नहीं है। अब समय आ गया है, जनता बारिक हिसाब लेगी। राजनांदगांव लोकसभा की जनता बघेल को ऐतिहासिक मतों से हराकर वापस पाटन भेजेगी।

सांसद संतोष पांडेय के घर चोरी का प्रयास, चोर को पकड़ने में नाकाम गार्ड

कवर्धा निवासी और राजनांदगांव लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी और वर्तमान सांसद संतोष पांडेय के घर में बीती रात चोरी का प्रयास किया गया है। घर की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी ने चोर को देख लिया। इसके बाद उसे पकड़ने के लिए पीछे भागा। चोर जवान को चकमा देकर फरार हो गया। ये पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। मामला सिटी कोतवाली के शिवाजी नगर का है। इस मामले में कोतवाली पुलिस की टीम पहुंची हुई थी। थाना से मिली जानकारी अनुसार सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच किया जा रहा है। पुलिस को शक है कि इस चोरी की वारदात में स्थानीय आरोपी शामिल होगा।

बूथ विजय संकल्प अभियान के तहत भाजपा ने लगाया हर घर झंडा

जगदलपुर। वन मंत्री केदार कश्यप लगातार लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए बस्तर के गांवों में जनसंपर्क कर रहे है। शनिवार को मंत्री कश्यप बूथ विजय संकल्प अभियान के तहत कई गांवों में लोगों से संपर्क किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की साय सरकार के विकास कार्यों की जानकारी क्षेत्र के लोगों को प्रदान की। इसके साथ ही वन मंत्री केदार कशप ने भानपुरी मंडल के तहत बूथ क्रमांक 240-करन्दोला, 247-चपका, 249- मुंजला, 251-देवड़ा और बूथ क्रमांक 263 सोनारपाल में देवतुल्य कार्यकर्ताओं के घरों में भाजपा का झंडा लगाया।

वनमंत्री केदार कश्यप ने कहा कि बूथ विजय संकल्प अभियान के तहत भाजपा के कार्यकर्ता घरों घर पहुँच रहे हैं। आज बूथ स्तर पर घर-घर जा कर सभी कार्यकर्ताओं ने भाजपा का झंडा लगाया है। पूरा देश भगवामय हो गया है जबकि कांग्रेस के पास चुनाव लड़ाने के लिये नेता बहुत दूर की बात है आज झंडा उठाने के लिए उनके पास कार्यकर्ता नही है।

मंत्री केदार कश्यप ने कार्यकर्ताओं से कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए इस बार फिर से मोदी की सरकार बनानी है। बस्तर से महेश कश्यप को भारी मतों से जिताना है। इसके लिए सभी कार्यकर्ता जुट जाए। वन मंत्री ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि कार्यकर्ता ही भाजपा की ताकत है। सभी विकसित राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे।

बिलासपुर सेंट्रल जेल में दो गुटों में खूनी झड़प पर जिला प्रशासन ने लिया एक्शन

बिलासपुर। बिलासपुर सेंट्रल जेल में कैंदियों के बीच गैंगवार का मामला सामने आया है। यहां होली के पहले ही दो गुटों के कैदियों ने एक दूसरे पर चम्मच और छड़ से हमला किया था। इन कैदियों ने चम्मच को चाकू की तरह तैयार करके एक दूसरे पर जानलेवा हमले का प्रयास किया। इस हमले में कई कैदी घायल हुए। अब इस मामले में 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है।

दरअसल, ये घटना बिलासपुर सेंट्रल जेल की है। यहां 22 मार्च की शाम को दो गुटों के कैदियों के बीच विवाद हो गया। ये विवाद बाद में मारपीट में तब्दील हो गया, जिसमें कई कैदी घायल हुए थे। जब इस मामले की जानकारी एसपी को हुई तब उनके निर्देश पर सिविल लाइन पुलिस की टीम जांच में जुटी। जांच के दौरान पता चला कि जेल अधीक्षक खोमेश मांडवी ने मामले को दबाने का प्रयास किया था। पुराने विवाद में दोनों गुटों के बीच लड़ाई होने की बात कही थी। मामले में 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। एक पक्ष के 7 और दूसरे पक्ष के 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है।

बिलासपुर सेंट्रल जेल में 22 मार्च की शाम वर्चस्व को लेकर दो गुटों में विवाद हुआ। दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। जेल में बंद अपराधी जेल के भीतर चम्मच और छड़ को घिसकर हथियार बनाकर छिपाकर रखे थे। 22 मार्च को विवाद के दौरान मौसीन खान, आसिफ खान, रफीक खान, इंदीत खान, अब्दुल अयाज खान और अब्दुल मेहताब खान ने मिलकर दूसरे गुट के अल्ताफ खान, फिरोज खान, जलील खान, कमर अली खान पर हमला कर दिया। इस दौरान कई कैदी घायल हो गए। सभी का उपचार कराया गया। जेल अधीक्षक खोमेश मंडावी ने इसे सामान्य विवाद बताया था। हालांकि जांच के दौरान दो गुटों के बीच गैंगवार का खुलासा हुआ। फिलहाल इस मामले में 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। साथ ही मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

शत प्रतिशत मतदान के लिए लोगों को किया जागरुक

जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आकाश छिकारा और पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला ने लोकतंत्र का महापर्व में मतदाताओं की शत प्रतिशत मतदान में भागीदारी हो जिसे लेकर जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे हैं। आज स्वीप कार्यक्रम के तहत केरा रोड से नेता जी चौक तक साइकिल रैली निकाली गई। जिसमें लोगों को निष्पक्ष एवं भय मुक्त मतदान करने का संदेश दिया गया। रैली में शामिल हुए अधिकारी कर्मचारी और आम नागरिकों को शपथ दिलाई गई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आकाश छिकारा ने कहा कि स्वीप कार्यक्रम के तहत कोसा कांसा कंचन वोट करेगा जन जन की थीम पर लोकतंत्र के महापर्व को लेकर लोगों के बीच जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की जानकारी दी जा रही है। लोगों को निष्पक्ष और भय मुक्त बिना किसी लोभ के वोट डालने की अपली की जा रही है। कलेक्टर आकाश छिकारा ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी नागरिकों को शपथ दिलाई।

भाजपा नेता के घर आईटी की दबिश

दुर्ग। जिले में मशहूर बिल्डर्स व भाजपा नेता के घर और दफ्तरों में आईटी की टीम ने दबिश दी है। दुर्ग के पुलगांव में स्थित अमर इंफ्रास्ट्रक्चर के ठिकानों पर आईटी के 12 से ज्यादा अधिकारियों ने दबिश दी है। यहां आठ गाड़ियों में 20 से ज्यादा अधिकारी पहुंचे हैं। मनोज राजपूत जमीन की खरीदी बिक्री के लिए जाने जाते हैं। मनोज राजपूत ने वर्तमान में एक छत्तीसगढ़ी फ़िल्म भी बनाया था, जिसमें वे मुख्य भूमिका में थे। वहीं उनके ही रिश्तेदार द्वारा उन पर शादी के नाम पर यौन शोषण करने का आरोप भी लगाया था। बताया जा रहा है कि छापेमारी में कई डिजिटल साक्ष्य के साथ-साथ अहम और प्रमुख दस्तावेज भी मिले हैं, जिसको लेकर आईटी की टीम पूछताछ कर रही है। अमर इंफ्रास्ट्रक्चर सड़क, पुल एवं पुलिया सरकारी टेडर्स के काम के लिए जाने जाते हैं, जिनमें तीन भाई 3 अलग-अलग फर्म में काम करते हैं। आपको बता दें कि अमर इंफ्रास्ट्रक्चर के मालिक चतुर्भुज राठी हैं, जो बीजेपी से जुड़े नेता हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की टिकट भी मांग रहे थे।

सीआरपीएफ जवानों से भरी एंबुलेंस पलटी, 12 घायल

जगदलपुर। बस्तर जिले के रतेंगा में शनिवार को सीआरपीएफ 188 बटालियन की एफ कंपनी के जवानों से भरी एंबुलेंस पलट गई। हादसे में 12 जवान जिसमें मनोहर तिवारी, विश्वजीत रॉय, राजीव बसुमतारी, बप्पा घोष, मंजीत बसुमतारी, तिलक राज, राजकुमार, करेन मशोहारी घायल शामिल हैं। इन घायलों में से 8 जवानों को ज्यादा चोटें आई हैं, जिनका डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में उपचार जारी है, 4 जवानों को लोहंडीगुड़ा में ही भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बस्तर जिले के ग्राम रतेंगा में सीआरपीएफ जवानों से भरी एंबुलेंस दुर्घटना में शामिल सभी जवान चुनावी ड्यूटी के लिए कोंडागांव जा रहे थे। इस हादसे में 11 जवान और ड्राइवर घायल हुए हैं। इसी दौरान मोड़ पर वाहन सड़क से नीचे उतरने से एक बड़े से गड्ढे में टायर फंसने से एंबुलेंस अनियंत्रित हो गई और हादसा हो गया। फिलहाल सभी जवान की स्थिति खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। विदित हो कि सुरक्षा कारणों के चलते जवान एंबुलेंस आदि वाहन का भी उपयोग करते है।

डेंटल क्लीनिक में लगी आग से मची अफरा- तफरी

कोरबा। कोरबा कोतवाली थाना के तहत पावर हाउस रोड स्थित एसएस प्लाजा के सामने स्थित विवेक डेंटल और सेंट्रल बैंक के पीछे हिस्से मकान में शनिवार को अचानक भीषण आग लग गई। जिस समय आग लगी उस दौरान मकान में किराएदार सोए हुए थे। इसी बीच ऊपरी तल के एक मकान से आग की लपटे निकलने लगी। आग की लपटें देखकर पावर हाउस रोड बिल्डिंग में रहने वाले लोगों में उस समय आपाधापी मच गई। आसपास के लोग जब तक आग को बुझाने का प्रयास करते आग पूरे मकान में फैल चुकी थी। आनन-फानन में कंट्रोल रूम पुलिस और होमगार्ड के दमकल को सूचना दी गई। होमगार्ड और सीएसईबी की दमकल मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास किया, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मकान के ऊपरी तल में लगे आग पर काबू पाने के लिए वहां तक पहुंचने में दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत उठानी पड़ी। दरअसल मकान के अंदर पिछली हिस्से पर आग थी और कोई दूसरा रास्ता वहां तक पहुंचने के लिए नहीं था।

अवैध शराब माफिया पर एक्शन, मामला दर्ज

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। अवैध तरीके से कच्ची शराब बनाने वाले व्यक्तियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग ने दो प्रकरणों में 56 लीटर कच्ची महुआ शराब और 585 किलोग्राम महुआ वाहन जब्त करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पेंड्रा से सटे बंधी गांव में लगातार कच्ची अवैध महुआ शराब बनाने और उसके बिक्री करने की शिकायत लगातार आबकारी विभाग के उप निरीक्षक दीपक सिंह ठाकुर को मिल रही थी। जिसके बाद आबकारी विभाग भी मौके की तलाश में था, तभी आबकारी विभाग को मुखबिरों से सूचना मिली कि पेंड्रा के बंधी गांव में रहने वाले रमेश साहू और सुजीत साहू बड़ी मात्रा में अवैध तरीके से देशी महुआ शराब बना रहे हैं। जिसके बाद आबकारी विभाग की टीम ने रमेश साहू और सुजीत साहू के ठिकाने पर दबिश दी और वहां से भारी मात्रा में देशी कच्ची महुआ शराब और महुआ के वाहन को जब्त किया है।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से शहीद की पत्नी को 10 साल बाद मिला न्याय

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से शहीद की पत्नी को 10 साल बाद न्याय मिला है। शहीद की पत्नी ने साल 2014 में न्याय के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। जिस पर दस साल के बाद साल 2024 में कोर्ट ने फैसला सुनाया।

बिलासपुर वेयर हाउस रोड में रहने वाले पुलिसकर्मी विजय कुमार बस्तर में नक्सलियों से संघर्ष के दौरान शहीद हो गए थे। 2 नवंबर 2007 को नक्सलियों के एंबुश में विजय कुमार समेत 10 पुलिसकर्मियों की जान चली गई थी। विजय की मौत के तीन माह बाद उनकी पत्नी अर्चना शुक्ला ने बच्चे को जन्म दिया। स्कूल दाखिला की उम्र होने के बाद बच्चे का एडमिशन विद्यालय में कराया गया। छत्तीसगढ़ पुलिस कर्मचारी वर्ग-असाधारण परिवार निवृत्ति नियम 1965 के नियम 5 के अनुसार शहीद जवानों के बच्चों की फीस

पुलिस विभाग देता है। ऐसे बच्चों की 21 वर्ष की उम्र पूरी होने तक उनकी शिक्षा पर होने वाली रकम दी जाती है। शहीद जवानों के बच्चों की फीस की रसीद जमा करने के बाद रकम का भुगतान विभाग की तरफ से किया जाता है।

शहीद जवान विजय कुमार की पत्नी ने भी बच्चे की स्कूल में एडमिशन के बाद भुगतान के लिए पुलिस विभाग ने रसीद जमा की। रसीद के आधार पर जवान की पत्नी को 18900 और 22800 रुपये का भुगतान पुलिस विभाग की तरफ से किया गया। लेकिन इस बीच पुलिस विभाग को ये पता चला कि बच्चे का जन्म जवान के शहीद होने के तीन महीने बाद हुआ जिसके बाद विभाग ने 26 अगस्त 2013 को भुगतान की हुई रकम की रिकवरी का आदेश जारी कर दिया। जिसके खिलाफ शहीद की पत्नी ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

इसी मामले में शहीद की पत्नी ने कोर्ट में ये भी बताया कि पुलिस विभाग ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, कोलकाता से जवानों का ग्रुप इंश्योरेंस करवाया था। जवानों की शहादत के बाद विभाग ने बीमा राशि के भुगतान के लिए कंपनी को पत्र लिखा। तब बताया गया कि जवान का नाम गलती से विजय कुमार की जगह विनोद कुमार शुक्ला हो गया था, इसे बाद में दुरुस्त कर लिया गया। जवान के शहीद होने के एक साल बाद 12 नवंबर 2008 को रकम विभाग को मिली, जिसे जवान की पत्नी को 27 जनवरी 2009 को मिली। लेकिन साल भर की देरी के बाद भी बीमा कंपनी ने एक साल की अवधि का ब्यान देने से इनकार कर दिया।

बीमा कंपनी ने हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ग्रुप इंश्योरेंस के लिए हुए एग्रीमेंट के अनुसार किसी तरह की विवाद की स्थिति में ऑर्बिटेशन के जरिए हल किया जाना है, इसी के तहत कंपनी की नीति के अनुसार देरी पर ब्याज देने का नियम नहीं है। शहीद जवान की पत्नी की तरफ से साल 2014 में लगाई याचिका मंजूर करते हुए जस्टिस गौतम भादुड़ी की बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने पुलिस विभाग की तरफ से फीस की रिकवरी का आदेश निरस्त कर दिया, साथ ही बीमा कंपनी को एक साल का ब्याज देने के लिए कहा।

नक्सलियों ने आईईडी विस्फोट में घायल ग्रामीण को 17 दिनों तक बंधक बनाकर रखने के बाद छोड़ा

बीजापुर। थाना नैमेड क्षेत्र अंर्तगत ग्राम इतावर में 11 मार्च को नक्सलियों द्वारा पुलिस को जान से मारने व नुकसान पहुंचाने की नीयत से लगाए गए आईईडी बम की चपेट में ग्रामीण गुड्डू लेकाम आ गया और बुरी तरह से घायल हो गया। नक्सलियों ने आईईडी विस्फोट में घायल ग्रामीण गुड्डू लेकाम को अगवाकर करीब 17 दिनों तक बंधक बनाकर अपने पास रखा। युवक के माता पिता से बातचीत के बाद नक्सलियों ने उस युवक को छोड़ दिया।

नक्सलियों के चंगुल से छूटने के बाद युवक के परिजनों ने उसे बीजापुर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, युवक की गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर उपचार के लिए रायपुर रेफर किया गया है। परिजनों के मुताबिक आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से युवक गुड्डू के दोनों पैर बर्बाद हो गए है। परिजनों का कहना है कि वह अपने पैर पर कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। पुलिस ने इस घटना को लेकर

मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है।

बीजापुर एसपी ने जितेंद्र यादव ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि नक्सलियों ने पुलिस को निशाना बनाने के लिए आईईडी प्लांट किया था जिसकी चपेट में एक युवक आ गया। इस बात की जानकारी युवक के परिवार वालों को लगी, जिसके बाद परिवार वालों ने नक्सलियों से मिलकर युवक को छुड़ाया और युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, युवक को बेहतर उपचार के लिए के लिए रायपुर भेज दिया है।

संक्षिप्त समाचार

स्टंट बाइकर्स के खिलाफ रायपुर पुलिस का एक्शन

रायपुर। राजधानी रायपुर में बाइक स्टंट का एक और मामला सामने आया है। नवा रायपुर के सूने सड़कों में स्टंट बाजी करने वाले युवकों को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस ने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें स्टंट करने वाले माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही स्टंट करने और तेज रफ्तार बाइक चलने से मना कर रहे हैं। शहर के 11 स्टंट बाजों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। आईटीएमएस नवा रायपुर में लगाए गए कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। स्टंट बाइकर्स का नवा रायपुर के सड़कों में स्पीड बाइक चलाने और स्टंट करने की शिकायतें सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रही थी। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो के आधार पर वीडियो में दिख रहे वाहनों का नवा रायपुर में लगाए गए कैमरों से फुटेज निकालकर वाहनों की पतासाजी कर 11 बाइक चालकों को नोटिस भेजकर कार्यालय में बुलाया गया था।

दपूम रेलवे से चलने वाली हमसफर एक्सप्रेस में दो अतिरिक्त कोच की सुविधा

रायपुर। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। यात्रियों के बेहतर यात्रा के लिए दो अतिरिक्त कोच की सुविधा दी गई है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली इन्दौर-पुरी-इन्दौर हमसफर एक्सप्रेस में सुविधा दी गई है। इसमें एक अतिरिक्त एसी3 कोच और एक अतिरिक्त स्लीपर कोच की सुविधा अस्थायी रूप से उपलब्ध कराई जा रही है। रेलवे प्रशासन की ओर से अधिकाधिक यात्रियों को कंफर्म बर्थ उपलब्ध कराने के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली गाड़ी संख्या 20917/20918 इन्दौर-पुरी-इन्दौर हमसफर एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त एसी3 कोच और एक अतिरिक्त स्लीपर कोच की सुविधा अस्थायी रूप से उपलब्ध कराई जा रही है। यह सुविधा गाड़ी संख्या 20917 इन्दौर-पुरी एक्सप्रेस में दो अप्रैल को और गाड़ी संख्या 20918 पुरी-इन्दौर एक्सप्रेस में चार अप्रैल को उपलब्ध रहेगी। इस सुविधा की उपलब्धता से इस गाड़ी में यात्रा करने वाले अधिकाधिक यात्री लाभान्वित होंगे।

बेमेतरा की दो छात्राओं का राष्ट्रीय साधन प्रवीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए चयन

बेमेतरा। बेमेतरा के स्वामी आत्मानंद शासकीय शिवलाल राठी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के कक्षा आठवीं के दो छात्राओं अनुष्का तिवारी एवं मोनिका वर्मा का चयन राष्ट्रीय साधन सह प्रवीण्य छात्रवृत्ति हेतु हुआ है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय साधन - सह-मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा (एनएमएमएसई) की परीक्षा में चयनित होकर दोनों मेधावी छात्राओं ने अपना एवं परिवार तथा विद्यालय का नाम रौशन किया। कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने दोनों छात्राओं को बधाई और शुभकामना दी। वर्ष 2023-24 में आयोजित एनएमएमएसईपरीक्षा हेतु जिला बेमेतरा से कुल 770 परीक्षार्थी उपस्थित हुए। 87 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए एवं 70 विद्यार्थियों ने चयन सूची में अपना स्थान बनाया। इस परीक्षा में चयनित प्रतिभागियों को प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती हैं, ताकि वह अपने सपनों को पूरा कर सके, अच्छे से अध्ययन कर सके। इस सफलता के लिए जिला शिक्षा अधिकारी एवं विद्यालय प्राचार्या ने चयनित छात्राओं को बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

भाजपा प्रत्याशी भोजराज के खिलाफ कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से की शिकायत

रायपुर। कांकेर लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी भोजराज नाग के द्वारा बालोद जिला के डौंडीलोहारा क्षेत्र में चुनावी सभा के दौरान अपने लोकसभा क्षेत्र में तंत्र-मंत्र और नींबू काट कर गांव की जन-समस्याओं को अंधविश्वास के माध्यम से दूर करने का प्रलोभन मतदाताओं को दिये जाने की शिकायत कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त से किया। ज्ञापन में कहा गया है कि वर्तमान समय में सम्पूर्ण भारत में आदर्श आचार संहिता लागू है ऐसे स्थिति में छत्तीसगढ़ के अन्तर्गत कांकेर लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी भोजराज नाग के द्वारा बालोद जिला के डौंडीलोहारा क्षेत्र में चुनावी सभा के दौरान अपने लोकसभा क्षेत्र में तंत्र-मंत्र और नींबू काट कर गांव की जन-समस्याओ को दूर करने का प्रलोभन मतदाताओ को दी जा रही है। इस प्रकार भाजपा प्रत्याशी द्वारा आम मतदाताओ को गुमराह कर अंधविश्वास भरी प्रलोभन दे कर मतदाताओं को छल पूर्वक अपनी ओर प्रभावित करने के उद्देश्य से उक्त अनर्गल वायदे कर वक्तव्य दिये है। जिससे की उक्त वायदे से निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता को दूषित होने की संभावनाओं से इंकार नही किया जा सकता है। जिसका विरोध छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी विधि विभाग करती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में चुनावी सभा में इस प्रकार का कृत्य न केवल आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, बल्कि औषधि और जादुई उपचार आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम 1954 और आईपीसी के तहत भी अपराध की श्रेणी में आता है। उपरोक्त वक्तव्य देने वाले कांकेर लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी भोजराज नाग के विरूद्ध तत्काल कानूनी/समुचित कार्यवाही किया जाए।

ज्ञापन सौंपने वाले में कांग्रेस विधि विभाग प्रदेश अध्यक्ष देवा देवांगन, कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता, प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा, अंकित कुमार मिश्रा, एम. नईम, मनोज कुमार सोनकर उपस्थित थे।

कांग्रेस सरकार ने 152% के रेट में बंदरबांट के लिए घटाई थी जमीन दरें

रायपुर। छत्तीसगढ़ में जमीन की गाइडलाइंस रेट पर 30 प्रतिशत की छूट का आदेश वित्तिय वर्ष 2023-24 के साथ 31 मार्च को समाप्त होने जा रहा है। 2019 में कांग्रेस सरकार ने जमीन की गाइडलाइन रेट में 30त्न छूट का आदेश दिया था। जिसे हर वित्तिय वर्ष के साथ आदेश जारी कर आगे बढ़ा दिया जाता साथ ही पिछले 5 वर्षों में गाइडलाइंस की दरों में बढ़ोतरी नहीं की गई।

वित्त एवं आवास मंत्री ओपी चौधरी ने बताया पिछली सरकार द्वारा ज़मीन के गाइडलाइंस दरों में दी गई छूट 31 मार्च को समाप्त हो जाएगी । गाइडलाइन दरों में पिछले 5 सालों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई जिसका नुकसान किसानों को हुआ । 30 प्रतिशत छूट समाप्त होने से अब किसानों को भूमि अधिग्रहण में फायदा होगा साथ ही भू स्वामियों को अब जमीन पर ज्यादा लोन की राशि प्राप्त होगी ।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा की कांग्रेस की सरकार ने 152त्न रेट में बंदरबांट करने के लिए और अपने चहेतों को ज़मीन देने के लिए गाइडलाइंस दरें घटाई। बीजेपी की

सरकार इसे आगे बढ़ने नहीं जा रही। भूमी अधिग्रहण में मिलने वाली राशि की गढ़ना गाइडलाइंस के दरों के आधार पर होती है। लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोगों को लोन भी गाइडलाइंस के आधार पर ही मिलता है। अब उन्हें ज्यादा लोन मिल पाएगा।

कांग्रेस के आदेश को खत्म करने के विरोध पर कहा मार्केट में ज़मीन की कीमत और गाइडलाइंस की दरों में भारी अंतर है। आदेश खत्म होने से सभी को फायदा होगा। इस गाइडलाइंस के जरिए कांग्रेस के लोगों ने सरकारी जमीनों को अपने नाम कराया है उनको धक्का लगा है।

कांग्रेस द्वारा महतारी वंदन योजना का पैसा 4 साल बाद देने के आरोप पर वित्त मंत्री ने कहा 2018 में कांग्रेस ने जनघोषणा पत्र में लिखा था की माता बहनों को 500 प्रति माह यानी 6000 प्रति वर्ष मिलेगा उसका पैसा उन्होंने 5 सालों में दिया नहीं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने मार्च से महतारी वंदन योजना की किस्त जारी करना शुरू कर दिया है। जब तक सरकार रहेगी माताओं बहनों को इसका लाभ मिलता रहेगा। कांग्रेस के नारी न्याय गारंटी के महतारी वंदन योजना पर भारी पड़ने पर वित्त मंत्री ने कहा की देश प्रदेश की वित्तीय हालत पर घोषणाएं की जाती है ताकि वो पूरा किया जा सके। कांग्रेस पार्टी को ये पता है वे सरकार नहीं बना रहे इसलिए ऐसे वायदे वो जनता से कर रहे है लेकिन देश की जनता झूठे वादों पर भरोसा करने वाली नहीं है। कांग्रेस ने इस निर्णय का विरोध किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर का कहना है इससे गरीबों का मकान बनाने का सपना अधूरा रह जाएगा। सरकार को निर्णय वापस लेना चाहिए। यह पूरी तरह से गरीब विरोधी निर्णय है।

छत्तीसगढ़ में ईवीएम पर सियासी रार

भूपेश ने पूछा मेरे सवालों से भाजपा को मिर्ची क्यों लगी?

दुर्ग। छत्तीसगढ़ में ईवीएम और बैलेट पेपर पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। राजनांदगांव लोकसभा सीट के कांग्रेस उम्मीदवार भूपेश बघेल शनिवार को दुर्ग के दौरे पर थे।इस दौरान उन्होंने एक बार फिर से बैलेट और ईवीएम का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मेरे ईवीएम पर सवाल करने के बाद बीजेपी को जोर की मिर्ची क्यों लग रही है। दुर्ग में भूपेश बघेल कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे थे।

भूपेश बघेल ने दावा किया कि किसी सीट पर अगर नोटा सहित 384 से ज्यादा प्रत्याशी होंगे तो वहां पर नियम है कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा। ऐसी सूरत में ईवीएम से चुनाव नहीं कराया जा सकता ऐसी बातें निर्वाचन आयोग की वेबासाइट में लिखा गया है। यह 303 नंबर के प्रश्न के जवाब में भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर कहा गया है।

भूपेश बघेल ने कहा यदि किसी लोकसभा सीट पर 384 प्रत्याशी चुनाव में खड़े होंगे तो निर्वाचन आयोग को बैलेट पेपर से ही चुनाव करवाना पड़ेगा। इसी बात को लेकर बीजेपी को बहुत जोर से मिर्ची लगी और उन्होंने मेरे खिलाफ शिकायत कर दी। फिर इस मामले में जांच हुई। इससे मालूम होता है कि ये लोग ईवीएम के सहारे किस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। सच में किसी सीट पर 384 प्रत्याशी यदि चुनाव मैदान में होंगे तो इनकी हार सुनिश्चित है।

भूपेश बघेल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार का चुनाव बेहद खास है। यह चुनाव कांग्रेस के लिए आखिरी चुनाव है। यदि तीसरी बार बीजेपी जीती तो समझ लोग लोकतंत्र नहीं बचेगा। आप 2029 का लोकसभा चुनाव भूल जाइए।

दुर्ग में 9 विधानसभा क्षेत्रों से कांग्रेसी जुटे थे। भूपेश बघेल ने दुर्ग से कांग्रेस के उम्मीदवार राजेंद्र साहू को जीत दिलाने की अपील की। इस दौरान भूपेश बघेल के साथ बिलासपुर लोकसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र सिंह यादव भी मौजूद थे। भूपेश बघेल के इन आरोपों पर अब देखना होगा कि बीजेपी क्या कहती है।

एक अप्रैल से जमीन की रजिस्ट्री कराना पड़ेगा महंगा

रायपुर। छत्तीसगढ़ में एक अप्रैल से जमीन की रजिस्ट्री कराना महंगा हो जाएगा। जमीन की रजिस्ट्री में 30 फीसदी तक की मिल रही छूट योजना कल यानी 31 मार्च को खत्म हो जाएगी। पिछली कांग्रेस सरकार ने 30 प्रतिशत छूट देने के बाद रजिस्ट्री फीस 0.8 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 फीसदी कर दिया था, लेकिन वर्तमान बीजेपी सरकार ने पिछली पंजीयन शुल्क वृद्धि को जारी रखा है। लोगों को गाइडलाइन दर पर रजिस्ट्री कराना होगा और 4 फीसदी रजिस्ट्री फीस देनी होगी।

पिछली भूपेश सरकार ने 5 साल पहले रजिस्ट्री में 30 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान किया था। यह अवधि अब समाप्त होने के कारण लोगों को 100 प्रतिशत की दर से पंजीयन शुल्क देना पड़ेगा। । इस मामले में वित्त मंत्री ओपी चौधरी का कहना है कि गाइडलाइन जमीनों के रेट में 30 फीसदी छूट समाप्त होने पर छत्तीसगढ़ के खजाने में एक हजार करोड़ तक एक्स्ट्रा राजस्व मिलेगा। इससे सबसे ज्यादा फायदा

किसानों को मिलेगा। जमीन अधिग्रहण होने पर लोगों को जमीन की गाइडलाइन रेट कम होने से उन्हें कुल रकम में एक तिहाई रकम का नुकसान हो रहा था। जिस जमीन का मूल्य 10 लाख रुपए है, उसे अधिग्रहण पॉलिसी के तहत चार गुना मतलब 40 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए था। गाइडलाइन में जारी छूट की वजह से उन्हें 30 लाख रुपए ही मिल रहे थे।

उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने 30 प्रतिशत छूट दी थी, जो 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। फिलहाल आचार संहिता की वजह से कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है।

जादूगर की तोते में तो भाजपा की जान ईवीएम में : कांग्रेस

रायपुर। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के ईवीएम को लेकर दिए बयान के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाई हुई है। मामले में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। आरोप-प्रत्यारोप लगाकर निशाना साध रहे हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी नेताओं की ओर से ईवीएम के पक्ष में की जा रही बयानबाजी यह साबित करती है कि उसकी जान ईवीएम में बसती है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जैसे जादूगर की जान तोते में होती है, वैसे ही बीजेपी की जान ईवीएम में बसती है। जब भी ईवीएम के खिलाफ कोई तार्किक तथ्य, कोई बयान आता है, तो भाजपाई तिलमिला जाते हैं। ईवीएम के खिलाफ बोलने वाले को राष्ट्रद्रोही साबित करने में लग जाते हैं। आखिर बीजेपी बैलेट पेपर से चुनाव कराने से क्यों डरती है?

शुक्ला ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव प्रणाली की निष्पक्षता और विश्वसनीयता दोनों ही सर्वोपरि होनी चाहिये। आज देश के नागरिकों, मतदाताओं और प्रबुद्धजनों का एक बहुत बड़ा वर्ग है, जो लगातार ईवीएम की

कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है। इन सवालों का समाधान होना चाहिये न कि इन सवालों को बहुमत के अतिवाद में दबाया जाना चाहिये। देश के सभी प्रमुख विपक्षी दल ईवीएम के साथ पचास फीसदी वीवीपैट पर्चियों का मिलान करवाना चाहता है तो इसका भाजपा क्यों विरोध कर रही है? भाजपा बताएं निष्पक्ष चुनाव होने देने में उसको डर क्यों लग रहा है?

उन्होंने कहा कि बीजेपी जब विपक्ष में थी तब ईवीएम का विरोध करती थी। केन्द्र में मोदी सरकार बनने के बाद से ही अचानक भाजपा ईवीएम की समर्थक बन गयी। भाजपा की केन्द्र सरकार बनने के बाद लगातार ईवीएम की निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं। कांग्रेस सहित देश के 17 राजनैतिक दलों के लोगों ने ईवीएम से चुनाव कराने का विरोध करते हुये केन्द्रीय निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपा था। देशभर में ईवीएम के खिलाफ वातावरण है।

उन्होंने इनकम टैक्स विभाग की ओर से कांग्रेस को 1 हजार 823.08 करोड़ रुपए जमा करने की नोटिस को केंद्र सरकार की तानाशाही रवैया बताया है। कहा कि, देश में लोकसभा चुनाव के समय प्रमुख विपक्षी दल को संसाधनविहीन करने की केंद्र की साजिश है। आरोप लगाया कि मोदी को यह पता चल चुका है कि उनके खिलाफ देश में माहौल है, उनकी विदाई की बेला नजदीक है तो विपक्ष को चुनाव लड़ने से रोकने के लिये इनकम टैक्स विभाग को आगे कर दिया है। मोदी सरकार लोकतंत्र विरोधी षड्यंत्र करके विपक्षी दलों के सीमित संसाधनों को भी छीनने का काम कर रही है। कांग्रेस की पिछली सरकारों ने 70 सालों से निष्पक्ष चुनाव और स्वस्थ लोकतंत्र की जो छवि बनाई थी, केंद्र सरकार उसके खिलाफ काम कर रही है। भाजपा ने विपक्षी दलों से साधन, संसाधन छीनकर एकाधिकार स्थापित करने का षड्यंत्र रचा है।

एसीबी-ईओडब्लू ने महादेव सट्टा मनी लॉन्ड्रिंग में जांच की तेज

ईडी ने सेंट्रल जेल में की आरोपियों से पूछताछ

रायपुर। छत्तीसगढ़ में महादेव एप मामले को लेकर ईडी ने आरोपियों से जेल में पूछताछ की है। शुक्रवार को ईडी की टीम ने रायपुर जेल में बंद पूर्व सीएम भूपेश बघेल के ओएसडी के अलावा एएसआई चंद्रभूषण वर्मा और आरक्षक भीम सिंह से जेल में पूछताछ की है। कोर्ट ने इस मामले में 2 अप्रैल तक पूछताछ की इजाजत दी है। सूत्रों की माने तो ईडी ने इस मामले में सट्टेबाजी को लेकर शामिल लोगों, सट्टेबाजी गिरोह के संरक्षण देने के लिए पैसे लेने वाले लोग और आरोपियों ने किन लोगों को पैसे दिए हैं,इस बारे में पूछताछ की।

वहीं ईओडब्ल्यू ने रायपुर, दुर्ग और कांकेर में तैनात तीन पुलिसकर्मियों को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। मिली जानकारी के मुताबिक एसीबी-ईओडब्ल्यू के नए चीफ अमरेश मिश्रा ने ईडी की रिपोर्ट से दर्ज सभी मामलों की जांच शुरू करने के निर्देश दिए हैं। अमरेश

मिश्रा ने जांच के लिए अलग-अलग टीमें गठित की हैं। इसमें पुराने अधिकारियों ने भी मदद की ली जा रही है। महादेव सट्टा मामले की जांच डीएसपी सुरेश ध्रुव को सौंपी गई है। उनके साथ कुछ टीआई और एसआई भी हैं। यही टीम पूछताछ के लिए रायपुर जेल पहुंची थी। जेल में सबसे पहले एएसआई चंद्रभूषण वर्मा, भीम सिंह यादव और कारोबारी सतीश चंद्राकर से पूछताछ की गई है। बाकी आरोपियों से भी पूछताछ की जा चुकी है। जल्द ही उनका बयान दर्ज किया जाएगा।

भ्रष्टाचार की जांच कर रही है ईओडब्ल्यू- ईओडब्ल्यू इस बात की जांच कर रही है कि सट्टेबाजी का नेटवर्क चलाने और सुरक्षा देने के लिए किन अधिकारियों, कर्मचारियों और नेताओं ने पैसे लिए हैं। क्योंकि एएसआई चंद्रभूषण और सतीश चंद्राकर ने कई अधिकारियों और कर्मचारियों को पैसे देने की बात कबूली है। उसने किसके जरिए पैसे ट्रांसफर किए हैं? उन्होंने इसकी जानकारी ईडी को भी दी है। इन सभी से ईडी पूछताछ कर चुकी है। आरोपी के बयान और शिकायत में भी उसका जिक्र है। क्योंकि ईडी का फोकस मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला पर था।

मंत्री नेताम ने होली मिलन में लोगों को कराया भोज और पिलाई भांग: कांग्रेस

रायपुर। लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में जमकर शिकवा-शिकायत देखने को मिल रही है। दोनों एक दूसरे की शिकायत और खींचतान में लगी हुई हैं। एक दूसरे के लोकसभा प्रत्याशियों और नेताओं की शिकायत करने से पीछे नहीं हट रही हैं। प्रत्याशी पर दबाव बनाने और अयोग्य घोषित कराने के फिराक में लगातार मौके की तलाश में हैं। ताजा मामला छत्तीसगढ़ के मंत्री रामविचार नेताम का है। कांग्रेस ने नेताम की ओर से उनके गृहग्राम में होली मिलन कार्यक्रम में लोगों को भोजन कराने और भांग पिलाने के मामले की शिकायत चुनाव आयोग से की है। इसके अलावा रायपुर मेडिकल कॉलेज हाल में बीजेपी के सम्मेलन को लेकर भी चुनाव आयोग में शिकायत की है। दोनों मामले में दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।

कांग्रेस ने ज्ञापन में लिखा है कि वर्तमान में पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू है, ऐसे में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने अपने गृहग्राम में आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में लोगों को भोजन कराया और भांग पिलाई। यह

आदर्श आचार संहिता का घोर उल्लंघन है। कांग्रेस कमेटी विधि विभाग का कहना है कि छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री ने आदर्श आचार संहिता का मजाक उड़ाया है। बिना किसी डर और भय के आदर्श आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन किया है।

दूसरे शिकायत में कहा कि भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ ने 31 मार्च 2024 को पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम रायपुर में बीजेपी का सम्मेलन कराया। शासकीय भवन के ऑडिटोरियम पार्टी का कार्यक्रम कराना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। सम्मेलन कीअनुमति दिया जाना भी आदर्श आचार संहिता का मजाक उड़ाना है।

भूपेश के खिलाफ बोलने से मुझ पर हो सकता है हमला: रामकुमार शुक्ला

■ **कांग्रेस नेता ने की पुलिस से मांग- मेरी रिवॉल्वर वापस कर दो**

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ बोलने वाले कांग्रेस नेता ने पुलिस से अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर के वापस करने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने पुलिस को आवेदन पत्र लिखा है। कलेक्टर को लिखे इस आवेदन पत्र में पूर्व कांग्रेस नेता राम कुमार शुक्ला ने लिखा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ मैंने कुछ बातें कही है। उससे मुझे लगता है कि मुझ पर हमला हो सकता है। इसलिए मुझे आत्मरक्षा के लिए मुझे मेरे लाइसेंसी रिवाल्वर की जरूरत है, जो कि लोकसभा चुनाव के कारण मेरा रिवाल्वर इस समय सिविल लाइंस पुलिस थाने में जमा है।

उन्होंने खुद पर हमले की आशंका जताते हुए अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर वापस करने की मांग की है। अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। कुरूद से बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि भूपेश बघेल ने स्वीकार किया है कि कांग्रेस में स्लीपर सेल हैं। इसका मतलब है कि कांग्रेस एक आतंकी संगठन है। उस आतंकी संगठन से किसी को भी खतरा हो सकता है। रामकुमार शुक्ला के बयान में कहीं से भी अतिश्योक्ति

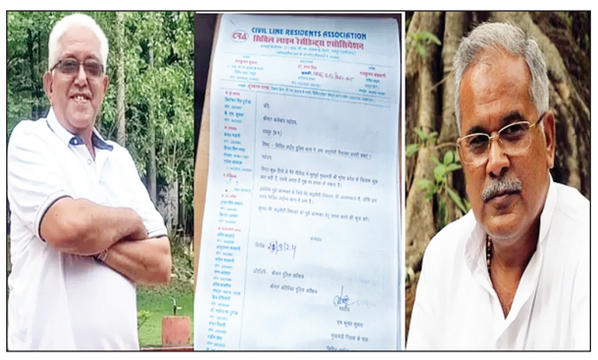

नहीं है। कोई भी स्लीपर सेल वाला उनकी हत्या कर सकता है। प्रशासन को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए।

इससे पूर्व रामकुमार शुक्ला ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर भूपेश बघेल को राजनांदगांव लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाने का विरोध किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि पूर्व सीएम भूपेश के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। उन पर महादेव एप केस में एफआईआर होने से कांग्रेस की फजीहत हुई है। इस वजह से कई कांग्रेस नेता और अधिकारी जेल में हैं। इसका असर ना केवल राजनांदगांव बल्कि सभी सीटों पर पड़ सकता है।

सुरेंद्र वैष्णव ने भी मांगी है सुरक्षा

दूसरी ओर भूपेश बघेल के खिलाफ राजनांदगांव में उनके ही सामने मंच पर पूर्व कांग्रेस सरकार के खिलाफ बोलने वाले सुरेंद्र वैष्णव ने भी अपने और अपने परिवार पर हमला होने की आशंका जताते हुए पुलिस से सुरक्षा की मांगी की थी। उन्होंने बघेल के सामने कहा था कि जब कांग्रेस की सरकार थी जब कार्यकर्ता आप से मिलने के लिए तरस जाते थे। कार्यकर्ताओं का कोई काम नहीं होता था। अब जब आप सत्ता में नहीं हैं तब आप से मिलना हो रहा है।

अरुण सिसोदिया ने मचाई थी खलबली

वहीं तीसरी ओर कांग्रेस के पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया को उनके संगठन विरोधी कृत्य के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उन पर अनुशासनहीनता और कांग्रेस की छवि धूमिल का आरोप लगा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने उन्हें नोटिस जारी कर तीन दिनों में जवाब मांगा था और उन्होंने जवाब दिया भी था।

एआईसीसी सदस्य अरुण सिसोदिया ने सार्वजनिक तौर पर कोष में अनियमितता का आरोप लगाया था। उनके बयान के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बवाल मच गया था। उन्होंने कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल और पूर्व सीएम भूपेश बघेल के सलाहकार विनोद वर्मा को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज को पत्र लिखा था। इस खत में आर्थिक गड़बड़ी को उजागर करते हुए आरोप लगाये थे। सबंधित नेताओं पर जांच के बाद कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने लिखा था कि दो महीने पहले पार्टी फंड में अनियमितता का मामला सामने आया था, जिसकी जांच के बाद मैंने ये खत लिखा है। सिसोदिया ने लेटर में सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा था कि रामगोपाल अग्रवाल और विनोद वर्मा के बेटे की कंपनी को 5 करोड़ 89 लाख रुपए का भुगतान करने से पार्टी को नुकसान हुआ है। इस पैसे का दुरुपयोग किया गया है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि %मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं, पार्टी में अगर सच बोलना बगावत है, तो मैं बागी हूं। अगर पार्टी कार्रवाई करती है, तो मैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के साथ खड़ा हूं।

दिल्ली में उप राज्यपाल का अगला कदम!

आदिति फडणीस

दिल्ली सरकार को 25 मई के पहले बर्खास्त किया जाएगा या उसके बाद? फिलहाल यही इकलौता प्रश्न है। दिल्ली में उसी दिन लोक सभा चुनाव हैं। उसके पहले कोई कदम उठाने पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दिल्ली की सीटें जीतने की संभावना पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बीच तानों की जंग जितनी लंबी चलेगी, उतने लंबे समय तक केजरीवाल को यह साबित करना होगा कि वह एक दमनकारी सरकार के राजनीतिक बंदी हैं, न कि एक भ्रष्ट व्यक्ति जैसा कि भाजपा दावा कर रही है। हर दूसरे दिन जेल में बंद मुख्यमंत्री के साथी बाहर यह घोषणा करते हैं कि उन्होंने जेल से क्या 'निर्देश' दिया है या क्या 'निर्णय' लिया है। इसकी प्रतिक्रिया में उप राज्यपाल ने जोर देकर कहा कि दिल्ली की सरकार जेल से नहीं चलेगी। हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि अनुच्छेद 239 एए और एबी के तहत दिल्ली के उप राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह भारत के राष्ट्रपति को सूचित करें कि ऐसी स्थिति बन गई है जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का प्रशासन संविधान सम्मत तरीके से से नहीं चलाया जा सकता है और वह सरकार को बर्खास्त करने की अनुशंसा कर सकते हैं। उन्हें इसमें इतना वक्त क्यों लग रहा है? लोक सभा में दिल्ली से आम आदमी पार्टी (आप) का कोई सांसद नहीं है। वहां सभी सात सांसद भाजपा के हैं। उप राज्यपाल के प्रतिनिधित्व वाली केंद्र सरकार का वास्तविक लक्ष्य है राज्य सरकार की विश्वसनीयता को प्रभावित करना। आमतौर पर यह काम पार्टी की प्रदेश इकाई का होता है। इस मामले में भाजपा की दिल्ली इकाई इतनी निष्प्रभावी है कि उसे इस काम के लिए संवैधानिक मुखिया की मदद लेनी पड़ी जबकि यह काम निर्वाचित नेताओं का था। विनय कुमार सक्सेना को 2022 में दिल्ली का उप राज्यपाल बनाया गया था। इससे पहले 2015 में उन्हें खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) का अध्यक्ष बनाया गया था। मूल रूप से कानपुर के रहने वाले सक्सेना ने अपना करियर राजस्थान की एक निजी कंपनी में सहायक अधिकारी के रूप में शुरू किया था। सन 1995 में वह धोलेरा बंदरगाह परियोजना के महा प्रबंधक बनकर गुजरात चले गए जिसे अदाणी पोर्ट्स लिमिटेड और जे के व्हाइट सीमेंट द्वारा विकसित किया जा रहा था। उन्हें न केवल सीईओ बनाया गया बल्कि परियोजना का निदेशक भी बना दिया गया। वर्ष 2000 से आज तक सक्सेना को अगर किसी से डर लगा है तो वह हैं मेधा पाटकर। सन 1990 के दशक में जब सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के विरुद्ध बाबा आमटे और मेधा पाटकर के नेतृत्व वाला नर्मदा बचाओ आंदोलन चरम पर था उस समय सक्सेना ने एक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना की जिसका नाम था नैशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज (एनसीसीएल)। उन्होंने आलेख प्रकाशित कराने आरंभ किए और पाटकर की गतिविधियों के विरुद्ध सशुल्क विज्ञापन देने शुरू किए। उन्होंने आरोप लगाया कि वह राष्ट्र विरोधी हैं तथा उन्हें संदिग्ध विदेशी माध्यमों से पैसे मिल रहे थे। पाटकर की मांगें एकदम साधारण थीं- बांध की ऊंचाई बढ़ाने से निश्चित तौर गुजरात और राजस्थान के कई जल संकट वाले इलाकों की प्यास बुझाने में मदद मिलती लेकिन इससे मध्य प्रदेश के हजारों लाखों लोगों को अपने घरों से उजड़ना पड़ता। बांध की ऊंचाई बढ़ाने तथा जल भराव वाले इलाके का विस्तार करने से पहले इन लोगों का पुनर्वास करना जरूरी था। इन दलीलों के सही गलत होने से परे नर्मदा बचाओ आंदोलन एक समय गुजरात में बदनाम हो गया था। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने अपने रुख के समर्थन में हरसंभव सहायता जुटाने की कोशिश की। राज्य सरकार की ओर से सक्सेना ने बीड़ा उठाया और पाटकर के खिलाफ मुकदमा लड़ा। बदले में पाटकर ने उनके खिलाफ अवमानना के मामले दायर किए जो अभी भी चल रहे हैं। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिय काम के लिए सक्सेना का समर्थन यहीं नहीं रुका। उनके स्वयंसेवी संगठन ने ही चिंतक आशिष नंदी के खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी।

कांग्रेस की मंद होती रोशनी के कारण

ललित गर्ग

देश की सबसे पुरानी एवं मजबूत कांग्रेस पार्टी बिखर चुकी है, पार्टी के कद्दावर, निष्ठाशील एवं मजबूत जमीनी नेता पार्टी छोड़कर अपनी सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, वह भी तब जब लोकसभा चुनाव सन्निकट है। कांग्रेस नेताओं का यह दलबदल आश्चर्य की बात हैं, पार्टी छोड़ने का जैसा सिलसिला चल रहा है, वह देश के इस सबसे पुराने दल की दयनीय दशा और स्याह भविष्य को ही रेखांकित करता है। हालांकि भाजपा और कुछ अन्य दलों के चंद नेता कांग्रेस की शरण में भी गए हैं, लेकिन इसकी तुलना में उसके नेताओं के पार्टी छोड़ने की संख्या कहीं अधिक है। प्रश्न है एक लोकतांत्रिक संगठन की यह दुर्दशा एवं रसातल में जाने की स्थितियां क्यों बनी? इसके कारणों की समीक्षा एवं आत्म-मंथन जरूरी है। कांग्रेस पार्टी लगातार न केवल हार रही है, बल्कि टूट एवं बिखर रही है, जनाधार कमजोर हो रहा है, इन बड़े कारणों के बावजूद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने न इसकी समीक्षा की, न विश्लेषण किया। कांग्रेस पर वंशवाद एवं पुत्रमोह का ठप्पा लगा हुआ है। पार्टी में आंतरिक प्रजातंत्र नहीं है। शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेने में अक्षम है। बहुसंख्यकों के कल्याण की कोई नीति नहीं है। तुष्टीकरण नीति भी उसके लिए घातक साबित हो रही है। इन बड़े कारणों के बावजूद पार्टी में सन्नाटा पसरे होने के कारण ही अनेक जिम्मेदार एवं कर्णधार नेता ही पार्टी छोड़कर जा रहे हैं या चले गये हैं। आज का कांग्रेसी शीर्ष नेतृत्व साम्प्रदायिक, असामाजिक, स्वार्थी, चाटुकारी एवं देश-विरोधी तत्वों के साथ इस तरह %ताना-बाना% हो गया है कि उससे निकलना मुश्किल हो गया है। सांप-छछूंदर की स्थिति है। न निकलते बनता है और न उगलते। कांग्रेस नेतृत्व सत्ता प्राप्ति की खुशफहमी और खोने के खतरे की फोबिया से ग्रस्त है।

कांग्रेस के नेताओं के कांग्रेस छोड़ने से पार्टी नेतृत्व को हैरान-परेशान होना चाहिए, लेकिन शायद ही ऐसा हो, क्योंकि राहुल गांधी आम तौर पर ऐसे नेताओं को डरपोक या अवसरवादी करार देकर कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं। वह और उनके करीबी यह देखने-समझने के लिए तैयार नहीं कि आखिर क्या कारण है कि एक के बाद एक नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते रवनीत सिंह का भाजपा में जाना इसलिए कांग्रेस के लिए एक बड़ा आघात है, क्योंकि पंजाब उन राज्यों में है, जहां कांग्रेस अपेक्षाकृत मजबूत दिखती है और भाजपा तीसरे-चौथे नंबर के दल के तौर पर देखी जाती है। बात पंजाब ही नहीं, महाराष्ट्र, हिमाचल एवं अन्य प्रांतों की भी ऐसी ही है। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि कांग्रेस छोड़ने वालों में कई ऐसे नेता भी हैं, जो गांधी परिवार के करीबी माने जाते थे, जैसे अशोक चव्हाण, मिलिंद देवड़ा, सुरेश पचौरी। इसके पहले राहुल गांधी की युवा ब्रिगेड के सदस्य कहे जाने वाले अधिकांश नेता भी कांग्रेस से विदा ले चुके हैं। कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं में एक बड़ी संख्या उनकी है, जो अपना स्वतंत्र राजनीति वर्चस्व एवं पहचान रखते हैं, वे अपने जनाधार के लिए जाने जाते हैं। गांधी परिवार के करीबी एवं चाटुकार नेताओं में बहुत कम ऐसे हैं, जो अपने बलबूते चुनाव जीतने की क्षमता रखते हों।

प्रश्न है कि कांग्रेस की यह दशा क्यों बनी? देश की विविधता, स्वरूप और संस्कृति को बांधे रखकर चलने वाले अतीत के कांग्रेसी नेता, जिनकी मूर्तियों और चित्रों के सामने हम अपना सिर झुकाते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं- वे अज्ञानी नहीं थे। उन्होंने अपने खून-पसीने से %भारत-माँ% के चरण पखारे थे। आज उनकी राष्ट्रीय सोच एवं जनकल्याण की भावना को नकारा जा रहा है, उन्हें %अदूरदर्शी% कहा जा रहा है। कांग्रेस में धीरे-धीरे जमीनी धरातल पर कार्य करने वाले बड़ी सोच वाले कार्यकर्ता कम हो गए और नेताओं के चापलूस बढ़ गए। ये चापलूस ही आगे बढ़े और कांग्रेस की टूट का कारण बने हैं। वक्त यह सब कुछ देख रहा है और करारा थपड़ भी मार रहा है। कांग्रेस विश्वसनीय और नैतिक नहीं रही और सत्ता विश्वास एवं नैतिकता के बिना ठहरती नहीं। शेरनी के दूध के लिए सोने का पात्र चाहिए। कांग्रेस अपना राष्ट्रीय दायित्व एवं सांगठनिक जिम्मेदारी राजनीतिक कौशल एवं नैतिकतापूर्ण ढंग से नहीं निभा रही। अंधेरे को कोसने से बेहतर था कि कोई तो पार्टी में एक मोमबत्ती जलाता। रोशनी करने की ताकत निस्तेज होने का ही परिणाम है कि वक्त ने सीख दे दी। इसी का परिणाम है कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की संख्या तेजी से बढ़ती चली जा रही है, उससे तो यह लगता है कि पार्टी छोड़ो जैसा कोई अभियान चल रहा है। राहुल गांधी भले ही यह दिखाएं कि कांग्रेस नेताओं के जाने से पार्टी की सेहत पर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच तो यह है अब फर्क पड़ता दिख रहा है। आने वाले लोकसभा चुनाव के परिणाम इस फर्क को और अधिक स्पष्ट कर देंगे। कुछ नेता चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं और कुछ तो प्रत्याशी घोषित होने के बाद अपने कदम पीछे खींच चुके हैं। कांग्रेस भले ही यह दिखा रही हो कि वह भाजपा का मुकाबला करने मे समर्थ है, लेकिन यह किसी से छिपा नहीं कि वह अपने नेतृत्व वाले मोर्चे इंडिया महागठबंधन को वैसा आकार नहीं दे सकी, जिसकी आशा की जा रही थी। इसके लिए कांग्रेस अपने अलावा अन्य किसी को दोष नहीं दे सकती। कांग्रेस का क्षरण इसलिए शुभ संकेत नहीं, क्योंकि भाजपा के समक्ष वही सही मायने में एक राष्ट्रीय दल है। अन्य राष्ट्रीय दलों में कोई भी ऐसा नहीं, जिसकी जड़ें देश भर में हों। लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष भी आवश्यक होता है, लेकिन सत्तापक्ष उसकी मजबूती की चिंता नहीं कर सकता।

कांग्रेस पार्टी में शीर्ष नेतृत्व कमजोर हो गया है। वंशवाद, परिवारवाद के कारण कांग्रेस पार्टी दिनोंदिन डूबती जा रही है। पहले कांग्रेस नेताओं के लिए लोककल्याण पहली प्राथमिकता होती थी, लेकिन आज मोदी-विरोध उसकी प्राथमिकता है। मोदी-विरोध के नाम पर वह कभी-कभी राष्ट्र-विरोध करने लगती है, उनकी इस प्राथमिकता में बदलाव आने से भी पार्टी कमजोर हुई हैं। कांग्रेस अपनी तुष्टीकरण की नीति की वजह से भी कमजोर हो रही है। अगर इसमें बदलाव नहीं करती है, तो उसकी हालत बद से बदतर हो जाएगी। इस बात का समझना होगा कि कोई भी दल बहुसंख्यकों को नाराज करके देश पर राज नहीं कर सकता। राहुल गांधी क्या बोलते है, क्या सोचते है, कोई स्पष्ट सन्देश ही नहीं मिल पाता। कांग्रेस में कोई निर्णय ऐसा लिया जाता है, जो निर्णय होता ही नहीं। लोग समझते ही नहीं कि क्या कहा गया है। इसी कारण कई नेता नेपथ्य में चले गये हैं पर आभास यही दिला रहे हैं कि हम मंच पर हैं। कई मंच पर खड़े हैं पर लगता है उन्हें कोई प्रोम्प्ट कर रहा है। बात किसी की है, कह कोई रहा है। इससे तो कठपुतली अच्छी जो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहती। जो करवाता है, वही करती है। कठपुतली के अलावा कुछ और होने का वह दावा भी नहीं करती। किसी परिवार में तो यह चल सकता है लेकिन एक राष्ट्रीय दल को ऐसे नहीं चलाया जा सकता। लम्हों की खता सदियों को भुगतनी पड़ती है। शीर्ष नेतृत्व की गलत सोच, गलत निर्णय, गलत प्रेरणा न केवल पार्टी को बल्कि राष्ट्र के ताने-बाने को उधेड़ देते हैं, ऐसा ही कांग्रेस में हो रहा है। समूचे देश में कांग्रेस के अपरिपक्व राजनीति एवं कुप्रबंधन के उदाहरण भरे पड़े हैं। ऐसी सूरत में सवाल उठता है कि 2019 में 52 सीट पर सिमट गई कांग्रेस क्या 2024 में हाफ सेंचुरी भी लगा पाएगी? ऐसा लगता है कि बीजेपी के 'कांग्रेस-मुक्त भारत' अभियान में कांग्रेस की नीतियां एवं नेतृत्व मोह सहयोगी बन रहे हैं।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

महोपनिषद् (भाग-43)

गतांक से आगे...

इस भयंकर नरक रूपी साम्राज्य में दुष्कृत रूपी मतवाले हाथी भ्रमण करते हैं। आशारूपी बाणों और कटारों से सुसज्जित इन्द्रियरूपी वैरियों को जीतना अत्यन्त मुश्किल है।

जो इन्द्रियरूपी वैरियों को अपने वशीभूत कर चुके हैं तथा जिन्होंने चित्त के अहंभाव को विनष्ट कर दिया है, उनकी भोग लिप्साएँ उसी प्रकार समाप्त हो जाती हैं, जैसे हेमन्त ऋतु में कमल का पौधा सूख जाता है। एकत्व के दृढ़ अभ्यास द्वारा जब तक मन को नियन्त्रित नहीं कर लिया जाता, तब तक ही रात्रि में बेताल की तरह हृदय में वासना टिकी हुई रहती है। विवेकशील व्यक्ति अपने मन को अभीष्ट सिद्धि के लिए सेवक के समान सभी प्रयोजनों की पूर्ति के लिए मन्त्रीरूप तथा सम्पूर्ण इन्द्रियों को स्वनियन्त्रित करने के लिए सामन्तरूप बना लेते हैं, ऐसा मेरा विचार है।

मेरे विचार से मनीषी का मन लालन करने के फलस्वरूप स्नेहमयी ललना-स्वरूप और पालन करने से पितृतुल्य है। शास्त्रानुकूल आचरण से, स्वयं के एकत्रित अनुभवजन्य ज्ञान प्रकाश से तथा विवेक बुद्धि से मनरूपी पिता परमसिद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है।

अति हृष्ट-पुष्ट, सुदृढ़, निर्मल, स्ववशीभूत, भली प्रकार चैतन्य तथा आत्मिक सद्गुणों से प्रखर तेजस्विता युक्त सुन्दर मनरूपी मणि हृदय में विराजमान है। हे ब्रह्मन्! बहुविध वासना-तृष्णा के कीचड़ से सने इस मनरूपी मणि को विवेक रूपी जल से निर्मल करके साधन सिद्धि के लिए चमकदार (परिष्कृत) बनायें। सद्विवेक का अवलम्बन लेकर, बुद्धि से यथार्थ सत्य का अनुसन्धान करके इन्द्रियरूपी वैरियों को तुम छिन्न-भिन्न कर पाओगे, इसी से संसार रूपी भवसागर से तुम पार उतरने में सक्षम हो सकोगे।

क्रमशः ...

शोषितों की आवाज भीमराव अंबेडकर को आज ही मिला था भारत रत्न

साल के 365 दिन इतिहास में किसी न किसी खास वजह से दर्ज है। आज 31 मार्च का दिन भी ऐतिहासिक है। आज ही के दिन देश के संविधान निर्माता डॉ भीमराव अंबेडकर को 1990 को मरणोपरांत सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ऐसा कर के देश और समाज के प्रति उनके अमूल्य योगदान को नमन किया गया। बाबासाहब भीमराव आंबेडकर ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था और जीवनभर सामाजिक भेदभाव के खिलाफ लड़ते रहे। आजादी के बाद उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई जब उन्हें राष्ट्र के संविधान निर्माण का दायित्व सौंपा गया।

बाबा साहेब महार जाति से आते थे जो कि उस समय अछूत माना जाता था। अंबेडकर को बचपन में ही समाज के विभेदकारी बर्ताव का सामना करना पड़ा था। उन्हें स्कूल में अलग बैठाया जाता था, ऊंची जाति के बच्चे उनसे ठीक से बात नहीं करते थे। अंबेडकर को ये बात काफी चुभती थी और उन्होंने उस अल्प आयु में ही समाज से इस विभेद को खत्म करने का प्रण ले लिया था।

अंबेडकर ने अपने जीवन में समाज से विभेद हटाने को अपना लक्ष्य बना लिया था और इसकी पूर्ति करने के लिए उन्होंने पढ़ाई को हथियार बनाया। बाबा साहेब बचपन से पढ़ाई में अव्वल आते थे और इसी का नतीजा था कि साल 1912 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में ऑनर्स करने के बाद वो आगे की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चले गए। अंबेडकर की विदेश में पढ़ाई का खर्चा बड़ौदा के शासक ने उठाया था। यहां पढ़ाई करने के बाद बाबा साहेब ने साल 1921 में लंदन स्कूल ऑफ इकॉनोमिक्स से पढ़ाई पूरी की। अंबेडकर ने पढ़ाई पूरी करने के बाद तमाम छात्रों की तरह नौकरी शुरू की, लेकिन बचपन में सामाजिक विभेद मिटाने की ली गई प्रतिज्ञा बार-बार उनके सीने में टीस मारती। इसी सबके बीच एक दिन उन्होंने सबकुछ छोड़ दिया और सामाजिक आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने 1936 में लेबर पार्टी का गठन किया। इससे पहले भी वह विभिन्न सामाजिक आंदोलनों का नेतृत्व करते आ रहे थे।

उन्होंने पत्र-पत्रिकाओं को न केवल प्रकाशित किया, वरन् उनमें क्रांतिकारी लेखनी से समाज को झकझोरा, राजनीतिक अधिकारों और दलितों के लिए सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत और भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।

बाद में जब यह तय हो गया कि देश 15 अगस्त, 1947 को आजाद होगा तो संविधान बनाने की अहम जिम्मेदारी उन्हें उनकी बुद्धिमत्ता के कारण मिली। उन्होंने उस समय भारत के लिए ऐसा संविधान बनाया जो समाज के हर वर्ग को बराबर सम्मान और आवाज देता है। देश के आजाद होने के बाद वह भारत के पहले कानून मंत्री बने। अंबेडकर के जीवन में एक बड़ी घटना साल 1956 में घटी तब उन्होंने हजारों लोगों के साथ बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अंबेडकर की मृत्यु उसी साल हो गई और उन्हें मरणोपरांत साल 1990 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से उन्हें नवाजा गया।

यूक्रेन ने अब भारत की ओर कदम बढ़ाए

अभिनय आकाश

भारत और रूस की दोस्ती कितनी मजबूत है इस बात को तो पूरी दुनिया जानती है। यही वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दोस्ती देखते बनती है। भारत किस तरह से रूस के साथ अपनी दोस्ती निभा रहा है ये तो मॉस्को भी मानता है। दोनों देशों के बीच आपस में इतनी बनती है और ऐसा तालमेल है कि दुनिया में न्यूक्लियर अटैक रोकने में भी भारत की मदद ली जाती है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर हाल ही में अमेरिकी मीडिया में खुलाया किया गया था कि किस तरह से यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक होने वाला था और उसे भारत की पहल के जरिए टाला गया। भारत की बात रूस मानता भी है। इस बात को यूक्रेन भी बखूबी समझ रहा है। यूक्रेन के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए हुए हैं। उनकी यहां पर कई दौर की बैठकों के साथ कई बड़े लोगों से मुलाकात भी हो रही है। वहीं अपने विदेश मंत्री के दौरे के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्दमीर जेलेंस्की ने भारत को लेकर एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि भारत आने वाले स्विस पीस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करेगा। रूस -यूक्रेन के बीत टेबल टॉक में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति को भारत के प्रधानमंत्री से काफी उम्मीदे हैं। हाल ही में उनकी पीएम मोदी से फोन पर बातचीत भी हुई थी।

यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा रूस के साथ चल रहे संघर्ष के बीच कीव के शांति प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर से मुलाकात की है। 28 मार्च को दक्षिण एशियाई देश की दो दिवसीय यात्रा शुरू करने वाले कुलेबा भारत और यूक्रेन के बीच संबंधों को मजबूत करना भी चाहते हैं। कुलेबा को अंतरराष्ट्रीय शांति शिखर सम्मेलन के लिए भारत का समर्थन मिलने की उम्मीद है, जिसे तटस्थ स्विट्जरलैंड संभवतः वसंत ऋतु में आयोजित करेगा।

सम्मेलन की तारीखों की अभी घोषणा नहीं की गई है। यूक्रेन ने रूस के साथ राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की के 10-सूत्रीय शांति प्रस्ताव के लिए समर्थन जुटाने के लिए शिखर सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनाई है। जनवरी में स्विस राष्ट्रपति वियोला एमहर्ड ने कहा कि उनका देश वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति के अनुरोध पर स्विट्जरलैंड शांति फार्मूले पर शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए सहमत हो गया है। ज़ेलेंस्की ने 2022 में इंडोनेशिया में जी20 शिखर सम्मेलन में 10 सूत्री शांति योजना का अनावरण किया था। प्रस्ताव में यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता को बहाल करना, रूसी सैनिकों की वापसी और शत्रुता को रोकना, सभी कैदियों और बंदियों की रिहाई, पर्यावरण संरक्षण, यूक्रेनी भोजन की शिपमेंट सुनिश्चित करना, अनाज, ऊर्जा सुरक्षा, यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी, रूसी युद्ध अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण की स्थापना, परमाणु सुरक्षा बहाल करना और युद्ध समाप्त करना शामिल है।

यूक्रेन शांति सम्मेलन में भारत की भागीदारी चाहता है। 20 मार्च को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने फोन कॉल के दौरान, ज़ेलेंस्की ने सम्मेलन में भारत की उपस्थिति पर जोर दिया था। एक्स को संबोधित करते हुए, यूक्रेनी राष्ट्रपति ने लिखा कि भारत को उद्घाटन शांति शिखर सम्मेलन में भाग लेते देखना हमारे लिए महत्वपूर्ण था, जो वर्तमान में स्विट्जरलैंड में तैयार किया जा रहा है। पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में कहा कि उन्होंने ज़ेलेंस्की को शांति के लिए सभी प्रयासों और चल रहे संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने के लिए भारत के निरंतर समर्थन से अवगत कराया था। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भारत हमारे जन-केंद्रित दृष्टिकोण द्वारा निर्देशित मानवीय सहायता प्रदान करना जारी रखेगा। नई दिल्ली ने यूक्रेन के साथ मास्को के युद्ध में तटस्थ रुख बनाए रखा है। भारत ने कई बार दोहराया है कि बातचीत और कूटनीति ही संघर्ष को सुलझाने का रास्ता है।

उम्मीद है कि कुलेबा भारतीय अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान शांति शिखर सम्मेलन का मुद्दा उठाएंगे। मामले से परिचित लोगों के अनुसार, भारत ने अभी तक स्प्रिंग शिखर सम्मेलन में अपनी भागीदारी के स्तर पर निर्णय नहीं लिया है। भारत में अगले महीने से शुरू होकर 1 जून तक होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उन्होंने कहा कि अगर इस अवधि के दौरान शिखर सम्मेलन होता है तो उच्चतम स्तर पर नई दिल्ली की उपस्थिति खतरनाक होगी। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि कौन से देश भाग लेंगे या रूस शिखर सम्मेलन का हिस्सा होगा या नहीं। रॉयटर्स के अनुसार, यूक्रेन को रूस की भागीदारी के बिना विश्व नेताओं का वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित करने की उम्मीद है। ज़ेलेंस्की ने जनवरी में स्विट्जरलैंड में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि हम दुनिया के उन सभी देशों के लिए खुले हैं जो हमारी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। इसलिए आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हम किसे आमंत्रित करते हैं। रूस ने यूक्रेन के नेतृत्व वाली पहल को गैर-स्टार्टर के रूप में खारिज कर दिया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट (एससीएमपी) की रिपोर्ट के अनुसार, लेकिन चीन और स्विट्जरलैंड यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से मास्को को वार्ता में आमंत्रित करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। पिछले हफ्ते स्विस राजधानी बर्न में चीन के राजदूत ने कहा था कि बीजिंग शांति सम्मेलन में भाग लेने पर विचार करेगा। इस महीने की शुरुआत में ग्रीक प्रधान मंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस ने पुष्टि की कि वह वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने पिछले अगस्त में सऊदी अरब में यूक्रेन पर एक सभा में कहा था कि हालांकि कई शांति सूत्र जारी किए गए हैं, लेकिन कोई भी दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य नहीं है और पूछा कि क्या सभी हितधारकों के लिए स्वीकार्य समाधान पाया जा सकता है।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, यूक्रेनी विदेश मंत्री अपने भारतीय समकक्ष के साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय साझेदारी और सहयोग पर भी चर्चा करेंगे। भारत-यूक्रेन अंतर-सरकारी आयोग का एक सत्र भी आयोजित होने वाला है। कुलेबा ने पहले कहा था कि कीव यूक्रेन के पुनर्निर्माण में भारत की भूमिका का स्वागत करेगा। उन्होंने अपनी यात्रा से पहले दिप्रिंट से कहा कि अब आर्थिक परियोजनाओं और निश्चित रूप से देश के पुनर्निर्माण में यूक्रेन के साथ जुड़ने के लिए भारत का स्वागत है। कुलेबा ने भारतीय कंपनियों से यूक्रेन के युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण में शामिल होने का आह्वान किया है। उनकी भारत यात्रा, सात वर्षों में किसी यूक्रेनी विदेश मंत्री की पहली यात्रा, ऐसे समय में हो रही है जब रूस अग्रिम मोर्चे पर प्रगति के लिए कमर कस रहा है। रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रम्प और कांग्रेस में उनके समर्थकों के प्रतिरोध के कारण कीव को संयुक्त राज्य अमेरिका से बहुत जरूरी सैन्य समर्थन का भी इंतजार है।

आज का इतिहास

1727 महान भौतिकशास्त्री आइजैक न्यूटन का 84 वर्ष की आयु में लंदन में निधन हुआ।
1736 अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के अलमहाउस में बेल्व्यू अस्पताल की स्थापना की गयी जो की अमेरिका का पहला सार्वजनिक अस्पताल था।
1814 नेपोलियन विरोधी सैनिकों ने पेरिस पर कब्जा कर लिया।
1822 इंडिपेंडेंस-ओटोमन सैनिकों के ग्रीक युद्ध ने चियोस द्वीप पर 20,000 से अधिक यूनानियों का नरसंहार शुरू किया।
1822 यूनान के स्वतंत्रता संग्राम के तुर्क सैनिकों ने 20 से अधिक 000 लोगों के नरसंहार का आरंभ चियोस द्वीप पर किया था।
1842 मिडलटन जंक्शन और ओल्डम शाखा रेलवे लाइन को उत्तरी पश्चिम इंग्लैंड के वेरनेस में खोला गया।
1854 अमेरिकी नौसेना के कमोडोर मैथ्यू सी। पेरी (जापानी चित्रण) और तोकुगावा ने संयुक्त रूप से कनागावा के कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए, जिसने अमेरिकी व्यापार के लिए जापानी बंदरगाहों को खोलने के लिए मजबूर किया।
1870 अमेरिका में पहली बार किसी अश्वेत नागरिक ने वोट दिया।
1889 एफिल टॉवर का उद्घाटन पेरिस में किया गया था, जो फ्रांस का एक वैश्विक केंद्र बन गया और दुनिया में सबसे पहचानने योग्य संरचनाओं में से एक है।
1889 पेरिस का मशहूर एफिल टावर आधिकारिक तौर पर खुला।
1901 काला सागर में 7.2 तीव्रता का भूकंप आया, जो क्षेत्र में अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप है।
1910 छह अंग्रेजी शहरों ने अपने प्रकार के पहले संघ के एकल काउंटी बोरोकॉल्ड स्टोक-ऑन-ट्रेंट बनाने के लिए समामेलित किया।
1917 अमेरिका ने 25 मिलियन डॉलर में डेनिश वेस्ट इंडीज खरीदा और उसका नाम वर्जिन आइलैंड रखा।
1930 सरकारी सेंसरशिप से बचने के लिए, हॉलीवुड फिल्म स्टूडियो ने उद्योग सेंसरशिप दिशानिर्देशों के अपने स्वयं के सेट की स्थापना की, जिसे हेस कोड के रूप में जाना जाता है।
1964 ब्राजील के सशस्त्र बलों ने ब्राजील के राष्ट्रपति जोओ गौलार्ट के एक ओवर थ्रो का नेतृत्व किया और एक सैन्य सरकार की स्थापना की जो 21 वर्षों तक चली।
1966 सोवियत रूस ने पहला चंद्रयान लूना-10 लांच किया।
1983 कोलंबिया के शहर पोपायन में आए विनाशकारी भूकंप में 500 लोगों की मौत हुई।

महिलाओं के विरुद्ध अनर्गल टिप्पणी से आखिर कैसे मिलेगी निजात

कमलेश पांडे

भारतीय राजनीति में महिलाओं के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी या बयानबाजी कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब एक सम्भ्रांत महिला दूसरी प्रतिस्पर्धी महिला पर कीचड़ उछाले, अनैतिक कटाक्ष करे...तो किसी का भी चिंतित होना लाजिमी है। सवाल है कि महिलाओं के विरुद्ध अक्सर होने वाली ऐसी अनर्गल टिप्पणी से आखिर कैसे निजात मिलेगी?

हाल ही में हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनोट और मंडी पर कांग्रेस की सोशल मीडिया प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत व गुजरात कांग्रेस के किसान राज्य संयुक्त समन्वयक एच एस अहीर की आपत्तिजनक पोस्ट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इसे महिला सम्मान के विरूद्ध बताया और चुनाव आयोग से शिकायत कर तत्काल कार्रवाई की मांग की।

वहीं, हिमाचल प्रदेश भाजपा ने भी चुनाव आयोग से शिकायत की है कि यह अपमानजनक टिप्पणी है, जो इंटरनेट मीडिया पोस्ट के रूप में प्रसारित की गई है। यह किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली पोस्ट है। यही नहीं, यह आदर्श आचार संहिता के अनिवार्य दिशानिर्देशों का भी उल्लंघन है। यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के साथ भारतीय दंड संहिता के तहत भी अपराध के दायरे में आती हैं। इनकी टिप्पणियां लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत परिभाषित भ्रष्ट आचरण की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं।

वहीं, हिमाचल प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इसे देवभूमि हिमाचल का अपमान बताते हुए कहा कि सुप्रिया श्रीनेत की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल, कंगना को लेकर पूरा विवाद तब खड़ा हुआ, जब मंडी सीट से भाजपा प्रत्याशी कंगना को लेकर कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टाग्राम अकाउंट से अभिनेत्री की तस्वीर के साथ एक आपत्तिजनक पोस्ट की गई, जिसमें लिखा हुआ था कि क्या भाव चल रहा है मंडी में, कोई बताएगा?

यह बात अलग है कि विवाद बढ़ते ही कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने अपने पोस्ट को हटा दिया और सफाई दी कि उनके मेटा (इंस्टाग्राम व फेसबुक) अकाउंट का संचालन करने वाले किसी दूसरे व्यक्ति से यह गड़बड़ी हुई है। वह किसी महिला को लेकर ऐसी आपत्तिजनक पोस्ट के बारे में सोच भी नहीं सकतीं। वह उस पैरोडी अकाउंट के विरुद्ध कार्रवाई करेंगी, जो उनके नाम का इस्तेमाल कर रहा है।

वहीं, सुप्रिया श्रीनेत की पोस्ट के जवाब में कंगना ने कहा कि, एक कलाकार के रूप में अपने करियर के पिछले 20 वर्षों में मैंने हर तरह की महिलाओं का किरदार निभाया है। हमें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रहों के बंधन से मुक्त करना चाहिए। हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जिज्ञासा से ऊपर उठना चाहिए। हर महिला गरिमा और सम्मान की हकदार है।

उधर, सुप्रिया श्रीनेत वाले मामले पर भाजपा नेता अमित मालवीय ने कहा कि अगर आपके (सुप्रिया श्रीनेत) अकाउंट से वही पोस्ट होती है जो पैरोडी अकाउंट पर पोस्ट होती है तो इसका मतलब है कि दोनों अकाउंट के एडमिन एक ही हैं। वहीं, तजिंदर बग्गा ने कहा है कि इन पोस्ट से कांग्रेस का महिला विरोधी चेहरा बेनकाब हुआ है। सुप्रिया श्रीनेत ने कांग्रेस का नेहरूवादी चेहरा दिखाया है। वहीं, शहजाद पूनावाला ने भी सुप्रिया श्रीनेत के पोस्ट को शर्मनाक बताया और कहा कि यह घिनौनेपन से भी आगे है। क्या मल्लिकार्जुन खरगे सुप्रिया श्रीनेत को हटाएंगे? हाथरस वाली लॉबी अब कहाँ है?

वहीं, राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक पोस्ट में कहा, %आयोग सुप्रिया श्रीनेत और एचएस अहीर के

अपमानजनक आचरण से स्तब्ध है, जिन्होंने इंटरनेट मीडिया पर कंगना के बारे में अभद्र व अपमानजनक टिप्पणी की। ऐसा व्यवहार असहनीय व महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध है। लेकिन सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ भाजपा नेता दिलीप घोष की टिप्पणियों के खिलाफ उसका स्टैंड क्या है? खुद कंगना रनौत का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें कंगना रनौत बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर को सॉफ्ट पोर्न स्टार कहती हुई सुनी जा रहीं हैं। ऐसे में सुलगता हुआ सवाल है कि जिस समाज में इस फूहड़ता की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, तो फिर भाजपा और कंगना सेलेक्टिव क्यों है? समय रहते ही स्पष्ट कर दें, तो बेहतर रहेगा।

क्योंकि एक तरफ तो कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने मंगलवार को एक प्रेस कांफ्रेंस में दो टूक कहा, सार्वजनिक चर्चा में ऐसी भाषा के लिए कोई जगह नहीं है और कांग्रेस का रुख इस मामले में हमेशा स्पष्ट रहा है। जबकि सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि जिसने भी यह किया है, यह एक गलती है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है और मामले को यहीं खत्म हो जाना चाहिए।

वहीं, दूसरी ओर बंगाल में भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद दिलीप घोष को एक वीडियो क्लिप में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पारिवारिक पृष्ठभूमि का मजाक उड़ाते हुए देखे जाने के बाद गत दिनों विवाद खड़ा हो गया। इस मामले में तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि दिलीप घोष की यह टिप्पणी %भाजपा के डीएनए% को दर्शाती है। साथ ही %एक्स% पर क्लिप साझा करते हुए पत्र लिखकर केंद्रीय चुनाव आयोग से इसकी शिकायत कर कार्रवाई की मांग की।

वहीं, आयोग ने बर्द्धमान-दुर्गापुर सीट से भाजपा उम्मीदवार घोष की टिप्पणी को लेकर जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी है। हालांकि, वायरल हुई इस वीडियो क्लिप की प्रामाणिकता की पुष्टि होनी अभी बाकी है। बता दें कि भाजपा की बंगाल इकाई के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष को तृणमूल के चुनावी नारे बांग्ला निजेर मेयेके चाई (बंगाल अपनी बेटी चाहता है) का मजाक उड़ाते हुए देखा जा सकता है।

उन्होंने कहा, जब वह (ममता) त्रिपुरा जाती हैं तो कहती हैं कि वह त्रिपुरा की बेटी हैं। जब वह बंगाल में होती हैं तो कहती हैं कि बंगाल की बेटी हैं। इसलिए पहले उन्हें स्पष्ट करने दीजिए, उनके पिता कौन हैं? गौरतलब है कि मेदिनीपुर लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद घोष तृणमूल के 2021 के चुनाव नारे %बांग्ला निजेर मेयेके चाई% का जिक्र कर रहे थे।

उनकी इस टिप्पणी पर बंगाल की महिला एवं बाल विकास मंत्री शशि पांजा ने कहा कि इस टिप्पणी पर उन्हें तुरंत माफी मांगनी चाहिए। वहीं, इस मुद्दे पर राष्ट्रीय महिला आयोग की खामोशी भी समझ से परे है। लोग पूछ रहे हैं कि बिलकिश बानो के दोषियों की रिहाई पर जिनका मुंह नहीं खुला, पहलवान बेटियों की दुर्दशा और दयनीय हालात पर जिनका मुंह नहीं खुला, मणिपुर की उस दुखद और अमानवीय घटना पर जिनका मुंह नहीं खुला, नेहा सिंह राठौर को मियां खलीफा से कंपेयर करने वालों पर जिनका मुंह नहीं खुला, वो अब कह रहे हैं कि सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना रनौत का अपमान किया है, जबकि सुप्रिया श्रीनेत ने पहले ही उस पोस्ट को डिलीट कर दिया है और बता भी दिया है कि यह उनकी सोशल मीडिया टीम की गलती थी। बावजूद इसके बीजेपी ने कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है।

सवाल फिर यही कि महिलाओं के विरुद्ध अनर्गल टिप्पणी के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग जैसी संस्थाएं पिक एंड चूज का रवैया अपनाएंगी तो फिर इस शर्मनाक सियासी प्रवृत्ति से निजात आखिर कैसे मिलेगी? यही नहीं, भाजपा और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियां भी पिक एंड चूज करके बयानबाजी करेंगी, तो फिर महिलाओं से जुड़े इस ज्वलंत सवाल का क्या होगा, जिस पर चुनाव आयोग से और राजनीतिक दलों से एक स्पष्ट और सर्वमान्य दृष्टिकोण की अपेक्षा की जाती है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो सियासत गर्त में चली जायेगी और उदंडता का महिमामंडन हर ओर होगा, जैसा कि आजाद भारत में एक सियासी परंपरा बन चुकी है।

लोकतांत्रिक मूल्यों के सम्मान से ही बचेगा लोकतंत्र

विश्वनाथ सचदेव

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे, यह सब जानते थे। सवाल सिर्फ कब गिरफ्तार होंगे का था। अब उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार कर लिया है। यह शब्द लिखे जाने तक उन्हें जमानत नहीं मिली है, और इसी तरह की पहली गिरफ्तारियों को देखते हुए यही लग रहा है कि जमानत आसान नहीं है। जनतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव का होना या चुनाव में जीतना ही पर्याप्त नहीं होता। चुनावों का सही तरीके से होना, चुनाव में भाग लेने के लिए सबको समान और उचित अवसर मिलना जनतंत्र के औचित्य की एक महत्वपूर्ण शर्त है। आज जो स्थितियां देश में बनती जा रही हैं, वे दुर्भाग्य से इस आशय का कोई आश्वासन नहीं दे रही हैं। किसी निर्वाचित मुख्यमंत्री का गिरफ्तार होना एक कथित आरोपी मात्र का गिरफ्तार होना नहीं होता। यदि किसी ने कोई अपराध किया है तो उसे अपने किए की सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन यदि सजा देने के नाम पर किसी प्रकार का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की जाती है तो उसे उचित नहीं माना जा सकता। यहां सवाल जनतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों का भी है। यह कहना तो गलत होगा कि देश में जनतंत्र की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन जनतंत्र को नए अर्थ देने की कोशिशों को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। समय पर चुनाव होने अथवा किसी नेता की लोकप्रियता के आधार पर जनतंत्र की सफलता अथवा औचित्य को नहीं नापा-परखा जा सकता। जनतंत्र का अर्थ होता है नागरिक के अधिकारों, और कर्तव्यों का भी, संरक्षण। जनतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता के मानकों पर व्यवस्था कितनी खरी उतरती है। असहमति का स्वीकार और सम्मान जनतंत्र को गरिमा और ताकत, दोनों देता है। क्या यह सब हम आज अपने देश में होता देख रहे हैं? इसके साथ ही मजबूत विपक्ष की महत्ता को समझा जाना भी जरूरी है। जनतंत्र में विपक्ष का काम मात्र आलोचना करना नहीं होता, विपक्ष को ईमानदार, सजग चौकीदार की भूमिका भी निभानी होती है। विपक्ष की सतत जागरूकता जनतंत्र के सफल और सार्थक होने की पहली और जरूरी कसौटी है। लेकिन दुर्भाग्य से हम अपने देश में विपक्ष को लगातार कमजोर किए जाने की कोशिशों को देख रहे हैं। स्वस्थ जनतंत्र का तकाजा है कि जनतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हो। जैसे न्याय होना ही नहीं, होते हुए दिखना भी चाहिए, वैसे ही जनतांत्रिक मूल्यों के प्रति सम्मान का भाव भी सम्मान किए जाने की प्रक्रिया के होते हुए दिखने की भी अपेक्षा करता है। आज जो कुछ हो रहा है उसे देखते हुए इस खतरे की आशंका स्वाभाविक है कि कहीं हम चुनावी एकाधिकारवाद की तरफ तो नहीं बढ़ रहे? यह सवाल उन सबके लिए महत्वपूर्ण है जो जनतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हैं।

राजस्थान में वसुंधरा समर्थक सांसदों का सफाया

रमेश सर्राफ धमोरा

राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के सभी समर्थक सांसदों के टिकट काट दिए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे समर्थक विधायकों के बड़ी संख्या में टिकट काटे गए थे। अब लोकसभा चुनाव में भी उनके समर्थकों का सफाया हो गया है। सिर्फ वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह को झालावाड़ से पांचवीं बार सांसद का टिकट मिला है।

श्रीगंगानगर सीट पर पांच बार के मौजूदा सांसद निहालचंद मेघवाल का टिकट काटकर अनूपगढ़ नगर परिषद की अध्यक्ष प्रियंका बैलान को प्रत्याशी बनाया गया है। प्रियंका बैलान प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ युवा मोर्चा में प्रदेश सचिव रह चुकी है। निहालचंद मेघवाल 1996, 1999, 2004, 2014 व 2019 में सांसद व 1998 में रायसिंह नगर से विधायक रह चुके हैं। उनके पिता बेगाराम चौहान 1977 में जनता पार्टी से व 1989 में जनता दल से सांसद व 1972 में रायसिंह नगर से स्वतंत्र पार्टी की टिकट पर विधायक रह चुके हैं। निहालचंद के भाई लालचंद चौहान भी 2003 में रायसिंह नगर से भाजपा के विधायक रह चुके हैं। ऐसे में निहालचंद मेघवाल का टिकट काटने का सिर्फ एक ही कारण रहा है। उनका वसुंधरा राजे गुट में होना। कांग्रेस ने वहां से कुलदीप इंदौरा को प्रत्याशी बनाया है।

चूरू से भाजपा के दो बार सांसद रहे राहुल कस्वां का टिकट काटने का भी मुख्य कारण वसुंधरा राजे के नजदीकी होना था। राहुल कस्वां चूरू में मजबूत जनाधार वाले नेता माने जाते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष रहे राजेंद्र राठौड़ के तारानगर से चुनाव हारने के चलते राहुल कस्वां का टिकट काटा गया है। राहुल कस्वां स्वयं 2014 व 2019 में चूरू से भाजपा टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। उनके पिता रामसिंह कस्वां चूरू से चार बार सांसद व सादुलपुर से विधायक रह चुके हैं। राहुल कस्वां के दादा दीपचंद कस्वां 1980 में सादुलपूर सीट से निर्दलिय व राहुल कस्वां की माता कमला कस्वां 2008 में सादुलपुर से भाजपा की विधायक रह चुकी है। उनकी माता

कमला कस्वां चूरू की जिला प्रमुख व पंचायत समिति प्रधान भी रही हैं। राहुल कस्वां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के छोटे भाई कुलदीप धनकड़ के दामाद है। फिर भी उनका टिकट महज राजेंद्र राठौड़ के विरोध के चलते काटा गया है। अब राहुल कस्वां कांग्रेस टिकट पर चूरू लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। झुंझुनू से नरेंद्र कुमार खीचड़ का टिकट काटकर उदयपुरवाटी से पूर्व में विधायक रहे शुभकरण चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया है। नरेंद्र खीचड़ भी वसुंधरा राजे के नजदीकी माने जाते रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले स्वयं वसुंधरा राजे ने उनको भाजपा में शामिल करवा कर 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा टिकट पर प्रत्याशी बनवाया था। 2019 में उन्हें वसुंधरा राजे की सिफारिश पर ही लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया गया था। झुंझुनू में कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शीशराम ओला के सुपुत्र विजेंद्र ओला को प्रत्याशी बनाया है।

जयपुर शहर लोकसभा सीट से भाजपा से दो बार लगातार सांसद व पूर्व जिला प्रमुख रहे रामचरण बोहरा का टिकट काटकर मंजू शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया हैं। रामचरण बोहरा वसुंधरा राजे के नजदीकी लोगों में शुमार होते थे तथा उनके हर कार्यक्रम में पूरी सक्रियता से भाग लेते थे। इसी के चलते उनका टिकट काटा गया है। हालांकि मंजू शर्मा भी भाजपा के तीन बार प्रदेश अध्यक्ष व भाजपा की सभी सरकारों में मंत्री रहे दिग्गज नेता भंवरलाल शर्मा की पुत्री है तथा 2008 में हवामहल सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी बृजकिशोर शर्मा से मात्र 580 वोटो से चुनाव हार गई थी। चर्चा है कि मंजू शर्मा को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सिफारिश पर भाजपा का प्रत्याशी बनाया गया है। दौसा से भाजपा सांसद जसकौर मीणा का टिकट काट दी गयी है। जसकौर मीणा पूर्व में सवाई माधोपुर से सांसद व बाजपेयी सरकार में राज्य मंत्री रह चुकी है। वह वसुंधरा राजे के नजदीकी मानी जाती है। दौसा सीट पर वर्तमान सांसद जसकोर मीणा अपनी पुत्री अर्चना मीणा को टिकट दिलवाना चाहती थी। वहीं राजस्थान सरकार में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा अपने भाई जगमोहन मीणा को टिकट दिलवाना चाहते थे। ऐसे में भाजपा ने वहां से चार बार विधायक व मंत्री रह चुके कन्हैयालाल मीणा को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने दौसा से मौजूदा विधायक मुरारीलाल मीणा को प्रत्याशी बनाया है।

करौली-धौलपुर लोकसभा सीट से भाजपा ने मौजूदा सांसद मनोज राजोरिया का टिकट काट कर पूर्व प्रधान इन्दु देवी जाटव को प्रत्याशी बनाया है। मनोज राजोरिया 2014 व 2019 में सांसद बनने में सफल रहे थे। उनका वसुंधरा राजे के प्रति जुड़ाव किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसी के चलते उनका टिकट काटा गया है। उदयपुर सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। यहां से लगातार दो बार सांसद रहे अर्जुनलाल मीणा का टिकट काटकर उनके स्थान पर परिवहन विभाग में कार्यरत मन्नालाल रावत को उम्मीदवार बनाया गया है। अर्जुन लाल मीणा वसुंधरा राजे गुट के माने जाते हैं। इसी के चलते उनका टिकट काट दिया गया है। कांग्रेस ने यहां से पूर्व जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा को प्रत्याशी बनाया है। बांसवाड़ा-डूंगरपुर लोकसभा सीट पर मौजूदा सांसद कनकमल कटारा का टिकट काटकर कांग्रेस से भाजपा में आए विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय को प्रत्याशी बनाया गया है। मालवीय प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पसंद माने जाते हैं। भीलवाड़ा लोकसभा सीट पर लगातार दो बार से सांसद बनते आ रहे सुभाष बहेड़िया का टिकट कटना भी तय माना जा रहा है क्योंकि यहां से अभी तक प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हो पाई है। जबकि कांग्रेस ने यहां से दामोदर गुर्जर को अपना प्रत्याशी बना दिया है। सुभाष बहेड़िया ने 2019 का लोकसभा चुनाव 611460 वोटो के अंतर से जीता था। इतनी बड़ी जीत होने के बावजूद भी बहेड़िया का टिकट क्लियर नहीं होने के चलते कयास लगाए जा रहे हैं कि पिछली बार अजमेर से कांग्रेस प्रत्याशी रहे रिजु झुंझुनूवाला के भाजपा में शामिल होने के चलते भीलवाड़ा से उनको भी प्रत्याशी बनाया जा सकता है।

'आजम' बनने की चाहत में कट गया सांसद एसटी हसन का पत्ता

अजय कुमार

पश्चिमी यूपी की मुस्लिम बाहुल्य सीट मुरादाबाद का मिजाज हमेशा यहां के मुस्लिम वोटर तय करते हैं। इसीलिये यहां बीजेपी आसानी से अपने कदम नहीं जमा पाती है। 17 बार हुए लोकसभा चुनाव में यहां से सिर्फ दो बार 1967 और 1977 में भारतीय जनसंघ का प्रत्याशी जीता था, जबकि 2014 में मोदी लहर में बीजेपी के कुंवर सर्वेश कुमार सिंह विजयी हुए थे। बाकी के चुनावों में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और जनता पार्टी या जनता दल का प्रत्याशी ही जीतता रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से एसटी हसन चुनाव जीते थे। एसटी हसन एक काबिल नेता हैं, उनकी सियासी महत्वाकांक्षा भी काफी अधिक है, लेकिन उनकी यह महत्वाकांक्षा आजम खान के रहते पूरी नहीं हो पा रही है। जब से पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी के कद्दार मुस्लिम चेहरा आजम खान कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े हैं तभी से एसटी हसन पश्चिमी यूपी में आजम खान की जगह अपने आप को स्थापित करने में लगे थे, इस बात का अहसास बुरे दौर से गुजर रहे आजम खान को भी था, लेकिन वह समय का इंतजार करते रहे और जब चुनाव का बिगुल बजा तो आजम ने अपनी ताकत दिखा कर एसटी हसन का घोषित हो गया टिकट कटवा दिया, ऐसा तब हुआ जब वह नामांकन भी कर चुके थे। समाजवादी पार्टी ने नामांकन के अंतिक दिन आखिरी घंटे में एसटी हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा को उम्मीदवार बना दिया है। यह सब तब हुआ जब अखिलेश यादव ने सीतापुर की जेल जाकर आजम खान से मुलाकात की थी, बताया जा रहा है कि आजम नाराज चल रहे थे और उन्होंने जनता से चुनाव का बहिष्कार करने तक का आहवान कर डाला था, जिसका सीधा असर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों पर पड़ता। आजम नाराज थे कि क्यों बिना उनकी मर्जी के मुरादाबाद और रामपुर का टिकट घोषित किया गया। इसी के बाद एसटी हसन का टिकट काट कर आजम पूर्व विधायक रूचि वीरा का मुरादाबाद से सपा का प्रत्याशी घोषित कर दिया गया।

पूर्व विधायक रुचि वीरा सपा के कद्दावर नेता आजम खान की करीबी मानी जाती है। एसटी हसन के समर्थकों ने आजम खान पर गंभीर आरोप लगाया है। समर्थकों का कहना है कि एसटी हसन का टिकट सपा नेता आजम खान के इशारे पर काटा गया है। फिलहाल अब मुरादाबाद सीट से आजम की करीबी रुचि वीरा सपा की अधिकृत उम्मीदवार हो गई हैं। इसको लेकर मुरादाबाद के जिलाधिकारी मानवेन्द्र सिंह ने आधिकारिक घोषणा भी कर दी है। वहीं, एसटी हसन ने नामांकन वापस लेने का ऐलान कर दिया है।

दरअसल, इस पूरे घटनाक्रम की कहानी सीतापुर जेल में शुरू हुई थी। सपा मुखिया अखिलेश यादव बीते 22 मार्च को आजम खान से मुलाकात करने सीतापुर जेल पहुंचे थे। उस मुलाकात के दौरान सपा के कद्दावर नेता आजम खान ने दो शर्तें रखी थीं, जिसमें से एक शर्त मुरादाबाद सीट से रुचि वीरा को उम्मीदवार घोषित करने की थी। रुचि वीरा आजम खान की बेहद करीबी मानी जाती हैं। साथ ही दूसरी शर्त आजम खान ने अखिलेश यादव को खुद रामपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की रखी थी, लेकिन उसके बावजूद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एसटी हसन का नाम 24 मार्च को मुरादाबाद सीट से घोषित कर दिया था।

मुरादाबाद से सांसद एसटी हसन को उम्मीदवार घोषित करने के बाद सपा के कद्दावर नेता आजम खान ने जेल में रहकर ही खेल कर दिया है। उधर, रामपुर सीट से उम्मीदवार घोषित न होने के चलते मंगलवार को रामपुर की सपा जिला इकाई ने बैठक कर दी। बैठक में रामपुर सीट से अखिलेश यादव के चुनाव न लड़ने की स्थिति में चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। मंगलवार को जहां रामपुर का सियासी पारा बढ़ रहा था तो वहीं दूसरी ओर आजम खान की करीबी रुचि वीरा लखनऊ पहुंच गईं। रुचि वीरा ने अखिलेश से मुलाकात करने के बाद अपना सिंबल लेकर मुरादाबाद के लिए रवाना हो गईं, क्योंकि अगले दिन यानी बुधवार को नामांकन का आखिरी दिन था। समाजवादी पार्टी के पहले से घोषित उम्मीदवार एसटी हसन ने अपना नामांकन किया था, लेकिन शाम होते ही उनके टिकट पर संशय पैदा हो गया था। आजम खान की करीबी रुचि वीरा को मुरादाबाद सीट से सिंबल मिलने और घोषित उम्मीदवार एसटी हसन का टिकट कटने की सूचना मिलते ही एसटी हसन के करीबी समर्थकों ने रुचि वीरा के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी थी। फिलहाल बुधवार को रुचि वीरा के नामांकन करने के बाद मुरादाबाद की पूरी तस्वीर साफ हो गई है। आजम खान की करीबी एवं पूर्व विधायक रुचि वीरा समाजवादी पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी हो गईं।

टिकट कटने के बाद सपा सांसद एसटी हसन ने कहा कि टिकट होना या न होना वो एसटी हसन की शख्सियत को खत्म नहीं कर सकता है। जो आइडियोलॉजी हमारी है, वो आइडियोलॉजी मुलायम सिंह यादव की थी और जो आइडियोलॉजी अखिलेश यादव जी की है, हम उसी के साथ हैं। एसटी हसन ने कहा कि मैं मुस्लिम वर्ग से आता हूं। अखिलेश ने ही मुझे पार्लियामेंट भेजा था। उन्होंने कहा कि अब सपा के उम्मीदवार नहीं हैं। अपना पर्चा वापस लेंगे। इसके साथ ही एसटी हसन ने कहा कि जब एक बार टिकट दे चुके थे तो कोई कारण तो नहीं था। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ही बेहतर बता पाएंगे कि टिकट क्यों काटा गया है। सपा नेता ने कहा कि अखिलेश पार्टी के नेता हैं, जिसको चाहें लड़ाएं, जिसको चहें न लड़ाएं। बहरहाल, आजम खान से सौ सुनार की एक लुहार की वाली कहावत चरितार्थ करते हुए हसन साहब को आइना दिखा दिया है।

अप्रैल के आखिरी हफ्ते में कांग्रेस तय करेगी कौन लड़ेगा अमेठी-रायबरेली से?

आशीष तिवारी

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अपने हिस्से में आईं दो सीटों को छोड़कर सभी पर उम्मीदवारों के नामों का एलान कर दिया है। लेकिन जिन दो सीटों पर अभी प्रत्याशी नहीं उतारे हैं, दरअसल वह अमेठी और रायबरेली ही हैं। कांग्रेस पार्टी से जुड़े सूत्रों की मानें, तो अब इन दो सीटों पर फैसला अप्रैल के आखिरी हफ्ते में हो सकता है। दरअसल रायबरेली और अमेठी में पांचवें चरण में चुनाव होना है, जिसकी चुनावी अधिसूचना 26 अप्रैल से लागू होगी। हालांकि कांग्रेस की ओर से इन दो सीटों पर प्रत्याशी घोषित न किए जाने से सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। आखिरकार कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की अपनी एक और सूची में रायबरेली और अमेठी को छोड़ दिया। कांग्रेस पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक रायबरेली और अमेठी सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर चर्चा तो की गई, लेकिन किसी प्रत्याशी के नाम पर अंतिम मुहर नहीं लगी है। बताया यही जा रहा है कि बुधवार को जब उत्तर प्रदेश के प्रत्याशियों की सूची घोषित हो रही थी, तो रायबरेली और अमेठी के प्रत्याशियों की सूची को पांचवें चरण में होने वाले मतदान के चलते होल्ड पर डाल दिया गया। सूत्रों के मुताबिक बैठक से पहले ही इस बात पर सहमति बन चुकी थी कि रायबरेली और अमेठी के प्रत्याशियों की घोषणा बुधवार को नहीं होगी। क्योंकि पांचवें चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव की नामांकन अंतिम तिथि तीन मई है और नामांकन भरने की प्रक्रिया 26 अप्रैल से शुरू होगी। इसलिए इन दो सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा 26 अप्रैल के आसपास ही हो सकती है। कांग्रेस पार्टी से जुड़े सूत्रों के मताबिक अभी तक जो कयास रायबरेली सीट पर लगाए जा रहे थे, उस पर फिलहाल कुछ ठोस रणनीति नहीं बनी है। यानी सोनिया गांधी की अनुपस्थिति में गांधी परिवार से किसी सदस्य को चुनाव लड़ाए जाने की चर्चाएं हो रही थीं। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल अब तक की स्थिति में गांधी परिवार से कोई भी इन दोनों सीटों से चुनाव लड़ने के लिए आगे नहीं आया है। हालांकि रायबरेली सीट पर तीन बार सर्वे कराया जा चुका है। इसमें एक सर्वे तो टेलीफोन के माध्यम से व्यक्तिगत तौर पर बड़ी संख्या में भी करवाया गया है। जानकारों की मानें तो अभी तक सर्वे में यह पुख्ता किया जा रहा कि गांधी परिवार के लिए यह सीट सोनिया गांधी की अनुपस्थिति में कितनी मजबूत है। हालांकि राजनीतिक जानकारों की मानें, तो रायबरेली और अमेठी में अब तक प्रत्याशियों के चयन में इस तरीके की देरी पहले कभी नहीं हुई। वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु त्रिवेदी कहते हैं कि अमेठी और रायबरेली यह दो सीटें पहले से ही तय प्रत्याशियों के साथ घोषित मानी जाती थीं। लेकिन इस बार जैसे ही सोनिया गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ने से मना किया और एक चिट्ठी लिखी, तो कयास लगाए जाने लगे कि गांधी परिवार से कौन प्रत्याशी होगा। इसके अलावा राहुल गांधी के चुनाव हारने के बाद अमेठी में कयास लगाए जाते रहे कि क्या दोबारा राहुल लड़ेंगे या नहीं? हिमांशु कहते हैं कि अब जब उत्तर प्रदेश में गठबंधन के हिस्से में आई कांग्रेस की सीटें तय हो चुकी हैं, तो अमेठी और रायबरेली से प्रत्याशी का घोषित न होना गांधी परिवार की विरासत वाली सीटों पर कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे रहा है। उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में चर्चाएं इस बात की भी हो रही हैं कि क्या इन दोनों सीटों पर इस बार गांधी परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। राजनीतिक जानकार और वरिष्ठ पत्रकार नसरुद्दीन कहते हैं कि एक तो कांग्रेस पहले से ही 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जबकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ता बीते कुछ समय से लगातार सभी सीटों पर मजबूती से मेहनत करते आए हैं। हालांकि सियासी गठबंधन में सभी सीटों पर चुनाव तो नहीं लड़े जा सकते हैं, लेकिन यह बात भी तय है गांधी परिवार से अगर कोई उत्तरप्रदेश में चुनाव नहीं लड़ता है, तो इसका असर कार्यकर्ताओं के मनोबल पर निश्चित तौर पर पड़ेगा।

वायआरएफ के स्पाई यूनिवर्स में क्रूर विलेन के रूप में बॉबी की एंट्री

सुपर एजेंट बनी आलिया से होगा मुक़ाबला

एनिमल में निर्दयी और क्रूर खलनायक 'अबरार हक' के किरदार के बाद, अब बॉबी देओल ख़तरानक विलेन के लिए मेकर्स की फ़र्स्ट च्वाइस बन गए हैं । ट्रेंड को फ़ोलो करते हुए ङ्कक्रन्न ने भी अपनी स्पाई यूनिवर्स में बॉबी देओल की खूंख़ार विलेन के रूप में वेलकम करने का फ़ैसला किया है । कहा जा रहा है कि, आदित्य चोपड़ा ने अपनी महिला केंद्रित स्पाई थ्रिलर, जिसमें आलिय भट्ट और शरवरी बाघ सुपर एजेंट के किरदार में नज़र आने वाली हैं, के क्रूर विलेन के लिए बॉबी देओल को साइन किया है । पिंकविला की एक रिपोर्ट के मुताबिक़, मेकर्स ने इस फिल्म के लिए बॉबी देओल के लिए एक विशेष लुक भी डिजाइन किया है।

पोर्टल द्वारा प्रकाशित इस रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से कहा गया है, एनिमल के बाद, बॉबी देओल के लिए यह एक और टेलर्ड निगेटिव रोल है । इस स्पाई थ्रिलर में बॉबी एक भयानक शैतानी ताकत का किरदार निभाएंगे जो आलिया भट्ट और शरवरी से आमना-सामना करने वाले हैं । कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है और बॉबी 2024 की दूसरी छमाही में फिल्म की शूटिंग शुरू करने के लिए उत्साहित हैं। सूत्र ने कथित तौर पर यह भी बताया कि इस फिल्म के लिए देओल अभिनेता के लिए एक विशेष लुक डिजाइन किया गया है ।

वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत सलमान खान की एक था टाइगर (2012) के साथ हुई, उसके बाद टाइगर ज़िंदा है (2017), और वॉर (2019), जिसमें ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ ने अभिनय किया। इसे शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम अभिनीत पठान और फिर सलमान खान और कैटरीना कैफ के साथ टाइगर 3 के साथ आगे बढ़ाया गया। अब, अगला प्रोजेक्ट वॉर 2 होगा जिसमें ऋतिक रोशन, एनटीआर जूनियर और कियारा आडवाणी अभिनय करेंगे और अयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित करेंगे। इसी के साथ वायआरएफ आलिया भट्ट और शारवरी वाघ के साथ स्पाई थ्रिलर की तैयारी भी शुरू हो चुकी है ।

क्रू को दो फिल्मों ने दी ओपनिंग के मामले में पटखनी

29 मार्च को बॉक्स ऑफिस पर तीन फिल्में रिलीज हुई हैं, जिसमें करीना कपूर खान, कृति सेनन और तब्बू की मचअवेटेड फिल्म क्रू है. इसके अलावा साउथ मूवी टिल्लू स्क्वैयर और हॉलीवुड मूवी गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर है. इन तीनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन धुआंधार ओपनिंग की. लेकिन क्रू बाकी दो फिल्मों से पीछे रहती हुई नजर आई क्योंकि टिल्लू स्क्वैयर और गॉडजिला एक्स कॉन्ग ने क्रू से ज्यादा ओपनिंग हासिल की है.

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, क्रू ने 8.75 करोड़ की ओपनिंग बॉक्स ऑफिस पर की है. वहीं वर्ल्डवाइड यह आंकड़ा 10 करोड़ के पार पहुंच गया है. जबकि टिल्लू स्क्वैयर ने पहले दिन 10.5 करोड़ की ओपनिंग अपने नाम की है. जो कि क्रू से ज्यादा है. वहीं वर्ल्डवाइड के मामले में भी साउथ की मूवी आगे निकली है.

क्रू ने 10 करोड़
टिल्लू स्क्वैयर 10.5 करोड़
गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर 13.8 करोड़ की कमाई पहले दिन भारत में की

हॉलीवुड फिल्म गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर की बात करें तो इसने 13.8 करोड़ की कमाई पहले दिन भारत में की है. वहीं वर्ल्डवाइड कमाई का तो हिसाब ही नहीं है.

बता दें, क्रू की चर्चा पिछले कई दिनों से थी, जिसका कारण फिल्म का दमदार प्रमोशन और कास्ट मानी जा सकती है. हालांकि पहले दिन के कलेक्शन के मामले में फिल्म ने अच्छी कमाई अपने नाम की है. हालांकि वीकेंड खत्म होने तक देखना होगा कि क्या रिपोर्ट सामने आती है.

अल्लू अर्जुन और डायरेक्टर सुकुमार ने पुष्पा 2 की रिलीज से पहले शुरू की पुष्पा 3 की प्लानिंग

तीन पार्ट में ख़त्म होगी पुष्पा फ्रेंचाइजी

सुकुमार द्वारा निर्देशित अल्लू अर्जुन स्टारर पुष्पा 2 भारतीय सिनेमा की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है । यह फिल्म 15 अगस्त 2024 को रिलीज होने के लिए तैयार है । इसके साथ उम्मीद जताई जा रही है कि यह दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बनाएगी । जहां पुष्पा 2 के लिए बेसब्री से इंतजार हो रहा है वहीं बॉलीवुड हंगामा को एक्सक्लूसिवली पता चला है कि, अल्लू अर्जुन और सुकुमार ने पुष्पा 2 की रिलीज से पहले ही पुष्पा 3 की प्लानिंग करना शुरू कर दिया है ।

पुष्पा एक ऐसा किरदार है जो हर मुश्किल से लड़ सकता है । सुकुमार और अल्लू अर्जुन को पुष्पा राज के किरदार से प्यार हो गया है और वे उसके एडवेंचर को तीन भागों में विस्तारित करना चाहते हैं । पुष्पा 2 का एक खुला अंत होगा जो पुष्पा 3 की ओर ले जाएगा और सुकुमार द्वारा राम चरण के साथ अपनी प्रतिबद्धता पूरी करने के बाद फिल्म फ्लोर पर जाएगी । सूत्र ने बॉलीवुड हंगामा को बताया। सूत्र ने आगे बताया कि पुष्पा 3 का नाम पुष्पाः द रोर है । पुष्पा की शुरुआत पुष्पाः द राइज से होती है, उसके बाद पुष्पाः द रूल होती है और पुष्पाः द रोर के साथ समाप्त होगी । पुष्पा 3 के लिए सब कुछ रेडी है लेकिन उचित स्क्रिप्टिंग पुष्पा 2 के नतीजे देखने के बाद ही शुरू होगी । यह कल्ट के साथ एक बेहतरीन फ्रेंचाइजी है ।

पुष्पा 2, जून 2024 तक खत्म होने की उम्मीद है, और अल्लू अर्जुन और सुकुमार दोनों 2024 की आखिरी तिमाही में अपनी-अपनी अगली फिल्मों की शूटिंग शुरू करेंगे ।

'बेला स्वान' क्रिस्टन स्टीवर्ट कभी नहीं करेंगी मार्वल मूवीज?

बेला स्वान यानी क्रिस्टन स्टीवर्ट! जिन्होंने ट्वाइलाइट मूवी से दुनियाभर में पॉप्युलैरिटी हासिल की। उन्हें आज भी फैंस बेला ही कहते हैं। सोचिए अगर वो मार्वल की किसी फिल्म में सुपरहीरो बने तो क्या माहौल होगा! यकीनन, फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन उनकी ये मुराद पूरी नहीं होगी, क्योंकि क्रिस्टन कभी मार्वल मूवीज में काम नहीं करेंगी। वो सिर्फ एक शर्त पर ही एमसीयू फिल्मों में नजर आएंगी, आइये जानते हैं, क्या है वो शर्त।

क्रिस्टन स्टीवर्ट ने पॉडकास्ट में मार्वल फिल्मों में काम करने को लेकर कहा, मैं शायद कभी मार्वल फिल्म नहीं करूंगी... ये वास्तव में एक डरावने सपने जैसा लगता है।

आपको एक व्यक्ति पर इतना पैसा और इतना भरोसा करना होगा... और ऐसा नहीं होता है। अजीब एक्सपीरियंस है, जहां आप इसके बारे में बिल्कुल भी पर्सनल महसूस नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए नहीं। हालांकि, 33 साल की क्रिस्टन ने आगे कहा कि अगर वो कभी मार्वल के तहत कोई प्रोजेक्ट साइन करती हैं, तो एक शर्त होगी।

शर्त ये होगी कि ग्रेटा गेरविग (बार्बी मूवी की डायरेक्टर) उसकी निर्देशक हों। वो कहती हैं, लेकिन शायद दुनिया बदल जाए, मैं यही कह रही हूं। मैं आपको मना कैसे कर सकती हूं, जब शायद एक दिन... अगर ग्रेटा गेरविग ने मुझसे मार्वल फिल्म करने के लिए कहा, तो मैं वो करूंगी।

मालूम हो कि ग्रेटा को पिछले साल रिलीज हुई बार्बी फिल्म के लिए एकेडमी अवॉर्ड नॉमिनेटेड राइटर-डायरेक्टर हैं। उन्होंने लेडी बर्ड और लिटिल वुमेन जैसी फिल्मों का भी डायरेक्शन किया है।

क्रिस्टन की भारत में भी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। उन्हें ट्वाइलाइट मूवी की सीरीज से खूब पॉप्युलैरिटी मिली थी। इसी फिल्म के हीरो रॉबर्ट पैटिनसन संग उनके अफेयर की चर्चा रही, लेकिन उन्होंने तब सबको हैरान कर दिया, जब खुलासा किया कि वो बाइसेक्सुअल हैं और उनकी गर्लफ्रेंड है।

इन फिल्मों में नजर आएंगी क्रिस्टन- वर्कफ्रंट की बात करें तो क्रिस्टन को साल 2022 में क्राइम्स ऑफ द फ्यूचर में देखा गया था। वो इस साल लव लाइज ब्लीडिंग, लव मी में देखा जाएगा। इसके अलावा वो 'Sacramento' में भी नजर आएंगी, जिसकी शूटिंग फिलहाल चल रही है।

ग्लोबल आर्ट म्यूज़ियम टेट मॉडर्न लंदन में सोनम की एंट्री ; 'यह हमारी आर्ट के लिए गर्व का पल है'

स्टाइल, फैशन और कला की विचारक नेता के रूप में अपने व्यापक प्रभाव के कारण सोनम कपूर को सर्वसम्मति से पश्चिम में भारत का सांस्कृतिक राजदूत माना जाता है। और यह खबर एक पारखी के रूप में उनकी स्थिति को और मजबूत करती है । दुनिया में आधुनिक और समकालीन कला के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक, टेट मॉडर्न ने सोनम को अपनी दक्षिण एशिया अधिग्रहण समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया है। सोनम एकमात्र भारतीय अभिनेता हैं जिन्हें टेट मॉडर्न द्वारा भारतीय और दक्षिण एशियाई कला को चैंपियन बनाने में इस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए शामिल किया गया है । उत्साहित सोनम कपूर ने पुष्टि की, मैं प्रतिष्ठित टेट मॉडर्न की दक्षिण एशिया अधिग्रहण समिति के सदस्य के रूप में शामिल होकर बेहद सम्मानित महसूस कर रही हूं। भारतीय और दक्षिण एशियाई कला के प्रति मेरा आकर्षण एक आजीवन यात्रा रही है, जिसके दौरान मैंने हर अवसर पर हमारे कलाकारों को चैंपियन बनाने का प्रयास किया है।

वह आगे कहती हैं, दक्षिण एशिया की कला की समृद्ध विरासत को अंततः वह वैश्विक मान्यता मिल रही है जिसकी वह हकदार है। एक भारतीय और दक्षिण एशियाई होने के नाते, हमारी कला को केंद्र स्तर पर आते देखना सौभाग्य की बात है। टेट मॉडर्न में यह भूमिका मुझे एक ऐतिहासिक मंच पर हमारी उल्लेखनीय कलाकृतियों और कलाकारों के लिए सक्रिय रूप से समर्थन और वकालत करने की अनुमति देती है।

सोनम आगे कहती हैं, यह न केवल मेरे लिए, बल्कि हमारे पूरे कला समुदाय के लिए गर्व का क्षण है, क्योंकि हम दुनिया भर में दक्षिण एशियाई कला की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।

श्रेयस तलपड़े और विजय राज की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर कर्तम भुगतम 17 मई को थिएटर में होगी रिलीज

मानव मानस की गहराइयों में एक रोलर-कोस्टर सवारी के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर कर्तम भुगतम 17 मई को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है । यह फिल्म पूरे भारत में 5 भाषाओं में रिलीज होगी । प्रशंसित फिल्म निर्देशक सोहम पी. शाह जिन्होंने पहले काल और लक बनाई, वह फ़िल्म को डायरेक्ट करेंगे । वहीं फ़िल्म में प्रतिभाशाली अभिनेता श्रेयस तलपड़े, विजय राज़, मधु और अक्षा परदासानी लीड रोल्स में नज़र आयेंगे । कर्तम भुगतम एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो दर्शकों को शुरू से अंत तक अपनी सीटों से बांधे रखेगी ।

ज्योतिष और कर्म के प्राचीन सार्वभौमिक सत्यों को जोड़ते हुए, फिल्म यह बताती है कि कैसे हर कार्य के कुछ निश्चित परिणाम होते हैं, जो सदियों पुरानी हिंदी कहावत जैसा करोगे, वैसा भरोगे (जैसे तुम बोओगे, वैसा ही काटोगे) को दोहराते हैं।

फिल्म के बारे में जानकारी देते हुए, निर्देशक सोहम पी. शाह ने कहा,कर्तम भुगतम एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है जो कर्म की जटिल कार्यप्रणाली से संबंधित है। शनि ग्रह द्वारा शासित एक वर्ष में, जिसे कर्म के भगवान के रूप में जाना जाता है, हमारी फिल्म ज्योतिष और मानव भाग्य के बीच गहरे संबंध की बात करती है ।

मुख्य अभिनेता श्रेयस तलपड़े ने फ़िल्म को लेकर अपना उत्साह ज़ाहिर करते हुए कहा, मेरे लिए, कर्तम भुगतम एक सार्वभौमिक सत्य का प्रतीक है - जो करोगे वही परिणाम के रूप में सामने आएगा। रहस्य इस बात की अप्रत्याशितता में निहित है कि कर्म कब और कैसे प्रकट होता है। जब मैंने फ़िल्म की कहानी सुनी और इसका बेहद इंटरेस्टिंग टाइटल सुना, मैं तुरंत फिल्म की ओर आकर्षित हो गया, फ़िल्म की कहानी इसके नाम की तरह ही अनोखी और रोचक है। गांधार फिल्म्स एंड स्टूडियो प्राइवेट द्वारा निर्मित कर्तम् भुगतम अपनी मनोरंजक कहानी, दिलचस्प पात्रों और रहस्यमय मोड़ के साथ दर्शकों को लुभाने के लिए तैयार है। 17 मई को रिलीज़ होने वाली कर्तम भुगतम पूरे भारत में हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज़ होगी।

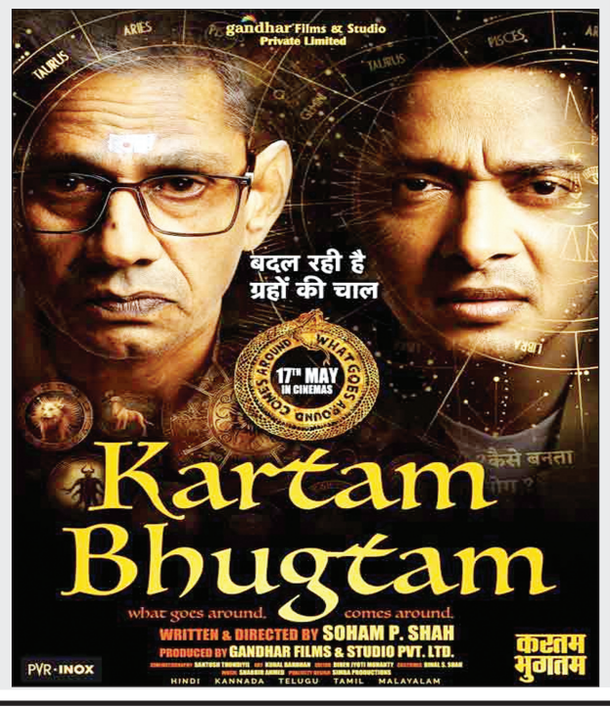

कृष 4 को स्टार्ट करने के लिए ऋतिक और राकेश रोशन की तैयारी फ़ाइनल स्टेज में

नई टेक्नोलॉजी की कहानी के साथ 2025 से शूटिंग शुरू करने की प्लानिंग

बॉलीवुड के लोकप्रिय सुपरहीरो फ्रेंचाइज़ी कृष की चौथी किस्त को लेकर फ़ैंस के बीच बहुत एक्साइटमेंट हैं । लेकिन मेकर्स की और से अभी तक कृष 4 को लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आई थी। लेकिन अब कृष 4 को लेकर अपडेट सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि, डायरेक्टर राकेश रोशन ने कृष 4 को फ़्लोर पर लाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। खबरों के मुताबिक़, राकेश रोशन और ऋतिक रोशन वॉर 2 की शूटिंग के साथ ही कृष 4 के लिए भी तैयार करेंगे। कृष 4 के लिए की जाने वाली तैयारी के लिए ऋतिक ने अपनी टाइमिंग फिक्स कर ली है । कहा जा रहा है कि, राकेश और ऋतिक रोशन इस बार एक ऐसी स्टोरी देना चाहते हैं, जो लोगों की सोच और उम्मीद से भी परे हो।

रिपोर्ट्स के अनुसार, ऋतिक अगले साल यानी 2025 में कृष 4 की शूटिंग शुरू करेंगे। फिल्म के प्लॉट को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर है कि इस बार की मूवी में इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल यानी कि गैलेक्सी पोर्शन को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर किया जा सकता है ।

इससे पहले फिल्म की कहानी में कहा गया था कि कृष 4 अंतरिक्ष यात्रा के दायरे का पता लगाएगी । रिपोर्ट में दावा किया गया है कि टीम ने खोजबीन की है और बाद में बहुत सारे विचारों को फ़ाइनलाइज किया है । निर्माताओं को यकीन है कि अगर कहानी काम नहीं करती है तो वे इसके साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। यही कारण है कि उन्होंने सुपरहीरो की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए सही कहानी खोजने में कई महीने लगा दिए हैं।

फिल्म फ्रेंचाइजी की शुरुआत फ़िल्म कोई मिल गया से हुई, जिसमें प्रीति जिंटा और रेखा मुख्य भूमिका में थीं । इसकी दूसरी किस्त कृष में ऋतिक के साथ प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिका में नज़र आईं थी । कृष 3 में भी यह जोड़ी बरकरार रही थी । और अब सभी को कृष 4 का बेसब्री से इंतज़ार है ।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

राष्ट्रपति ने राव, चरण सिंह कर्पूरी ठाकुर, स्वामीनाथन को भारत रत्न से नवाजा

नईदिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को यहां राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में पूर्व प्रधानमंत्रियों पी वी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, कृषि मंत्री एम एस स्वामीनाथन तथा बिहार के दो बार मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मरणोपरांत प्रदान किया। राव, सिंह, ठाकुर और स्वामीनाथन को दिए गए पुरस्कार उनके परिवार के सदस्यों ने लिए। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के लिए मुर्मू से यह सम्मान उनके पुत्र पी वी प्रभाकर राव ने स्वीकार किया। चौधरी चरण सिंह के लिए उनके पोते और राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने राष्ट्रपति से यह सम्मान स्वीकार किया। स्वामीनाथन की ओर से उनकी बेटी नित्या राव और कर्पूरी ठाकुर की ओर से उनके बेटे रामनाथ ठाकुर ने राष्ट्रपति मुर्मू से यह पुरस्कार लिया। इस समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री ने राजस्थान दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई दी

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को राजस्थान दिवस के मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं और कहा कि विकसित व आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में इस मरुधर प्रदेश की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ''राजस्थान दिवस पर राज्य के अपने सभी परिवारजनों को मेरी कोटि-कोटि शुभकामनाएं। अद्भुत ऊर्जा और उत्साह से भरे यहां के लोग राज्य के गौरव की एक नई गाथा लिखने में जुटे हैं। मुझे विश्वास है कि विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में राजस्थान की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। उल्लेखनीय है कि 30 मार्च, 1949 को जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर की तत्कालीन रियासतों के विलय के बाद ''वृहत्तर राजस्थान संघ'' बना था। यही राजस्थान की स्थापना का दिन माना जाता है।

मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का प्रधानमंत्री पर तीखा हमला

चेन्नई। तमिल पर हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक ताजा हमला करते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने उन पर पाखंड का आरोप लगाया और कहा कि यहां तक कि मोदी की आंखें भी उनके आंसुओं पर विश्वास नहीं करेंगी। उन्होंने सवाल किया कि प्रधानमंत्री, जो तमिलनाडु की पिछली यात्राओं के दौरान अंग्रेजी बोलते थे, अब हिंदी में क्यों बोलने लगे हैं। कल शाम, मोदी ने कहा कि उन्हें तमिल में बात न कर पाने का अफसोस है। कल की खबर में यह भी कहा गया कि अब से खूबसूरत तमिल शब्द वानोली को हिंदी शब्द आकाशवाणी में बदल दिया जाएगा। यहां तक कि मोदी की आंखों को भी उनके आंसुओं पर यकीन नहीं होगा। तो तमिल लोग इस पर कैसे विश्वास करेंगे? यह किस तरह का तमिल स्नेह है जब आप अपनी एक आंख से आंसू निकाल रहे हैं और दूसरी से आंसू बहा रहे हैं?

विपक्ष की महारैली में शामिल होंगे सीएम चंपाई सोरेन

नईदिल्ली। विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली का आयोजन करने जा रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरवाल की गिरफ्तारी सहित कई मुद्दों पर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। इस 'महारैली' को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी कि 4-5 मुद्दे हैं जिन पर यह रैली आयोजित की जा रही है। हमें झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और कई अन्य लोगों को भी नहीं भूलना चाहिए। इन्हें निशाना बनाया गया है। रामलीला मैदान में होने वाली इस रैली को लोकतंत्र के नजरिए से देखने की जरूरत है। यह किसी एक पार्टी की रैली नहीं है। झारखंड के सीएम चम्पाई सोरेन इस रैली में मौजूद रहेंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली महारैली में शामिल होने के लिए कई प्रदेश के नेता पहुंच रहे हैं। शनिवार को हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन दिल्ली पहुंच चुकीं हैं।

महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर अब बनाएंगे थर्ड फ्रंट

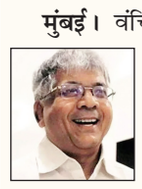

मुंबई। वंचित बहुजन अघाड़ी (वीबीए) प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत टूटने के बाद महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन के खिलाफ तीसरा मोर्चा बनाने का संकेत दिया है। अंबेडकर ने कहा कि हम भाजपा से मुकाबला करने के लिए राज्य में विभिन्न संगठनों के साथ जुड़ेंगे। हमारी अगली योजना 2 अप्रैल को चर्चा के बाद घोषित की जाएगी। अंबेडकर ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारांगे पाटिल के साथ उनकी बैठक हुई थी और वह प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से मराठा उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के इच्छुक थे। उन्होंने कहा, वीबीए की उम्मीदवार सूची को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। एमवीए नेताओं के साथ चर्चा के संबंध में अंबेडकर ने स्पष्ट किया कि हालांकि पार्टी को बैठकों में आमंत्रित नहीं किया गया था, लेकिन उसके दरवाजे खुले रहेंगे।

इंडी गठबंधन का आज दिल्ली में महारैली

कांग्रेस का आरोप- देश का लोकतंत्र खत्म कर रही भाजपा, पांच मुद्दों को लेकर रैली में भरेंगे हुंकार

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे विपक्ष भी सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर हमलावर हो रहा है। बता दें कि इंडी गठबंधन ने नई दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली का आयोजन किया है। 31 मार्च को महारैली आयोजित की गई है, जिसमें विपक्षी दलों के तमाम नेता शामिल होंगे।

इस रैली को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना है कि चार पांच मुद्दों को लेकर इसका आयोजन हो रहा है। इन मुद्दों में उन्होंने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे को प्रमुखता से रखा है। इसके साथ ही झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मामला भी रैली में उठाया जाएगा।

बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 31 जनवरी को जमीन घोटाले से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार किया था। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन भी कल की रैली में मौजूद रहेंगे। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि भाजपा ने जिन लोगों को निशाना बनाया है, हमें उन्हें बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए।

दिल्ली कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया का कहना है कि गठबंधन की कल लोकतंत्र बचाओ रैली होने जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि भाजपा देश के लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने में लगी है। उन्होंने कहा कि देश में किसान आंदोलन कर रहे, युवा परेशान हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, बलात्कार पीड़ित महिलाओं के आरोपियों को संरक्षण दिया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि इन सभी मुद्दों को राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उठाया तो विपक्षी एकता को तोड़ने के लिए विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार किया गया।

कर्नाटक के बागलकोट सीट को लेकर कांग्रेस में मचा बवाल!

बागलकोट कर्नाटक की महत्वपूर्ण सीटों में से एक हैं। हिंदू बहुल इलाके में फिलहाल बीजेपी राज कर रही है बागलकोट के सांसद पीसी गद्दीगौदर भापजा से हैं। इस सीज पर कांग्रेस भी कांटे की टक्कर देती हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए भी बागलकोट महत्वपूर्ण हैं। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष वीणा कशप्पनवर को उम्मीद थी कि वह इस बार कांग्रेस की टिकट से बागलकोट से चुनाव लड़ेंगी और भाजपा को हरा देंगी लेकिन कांग्रेस ने वीणा कशप्पनवर को टिकट नहीं दिया हैं। वीणा कशप्पनवर की अपनी एक साख हैं।

पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष वीणा कशप्पनवर, जो बागलकोट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस का टिकट नहीं दिए जाने से व्यथित हैं, ने अपनी समस्या का समाधान खोजने के लिए बुलाई गई बैठक के नतीजे पर नाराजगी व्यक्त की है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस (टीएनआईई) से बात करते हुए, टिकट वितरण पर भ्रम को खत्म करने के लिए गुरुवार को बेंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और अन्य पार्टी नेताओं की बैठक से वीणा कशप्पना को राहत नहीं मिली। इससे असंतुष्ट वीणा कशपना ने तटस्थ रहने का फैसला किया है और जल्द ही तय करेंगी कि लोकसभा चुनाव लड़ना है या नहीं। उन्होंने कहा कि एक दो दिन में मैं अपने समर्थकों की बैठक बुलाऊंगी। मैं अपने अगले कदम पर उनकी राय लूंगी। वीणा कशप्पनवर ने कहा, बैठक के नतीजे के आधार पर मैं तय करूंगी कि चुनाव लड़ना है या नहीं, लेकिन अभी मैं अपने रुख पर तटस्थ हूं।

कांग्रेस विधायक विजयानंद कशप्पनवर की पत्नी वीणा पार्टी द्वारा मंत्री शिवानंद पाटिल की बेटी संयुक्ता पाटिल को टिकट दिए जाने से काफी नाराज हैं। शिवानंद पाटिल विजयपुर के रहने वाले हैं। वीना न सिर्फ बागलकोट की रहने वाली थीं बल्कि पार्टी से टिकट भी पाना चाहती थीं क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में मौजूदा सांसद पीसी गद्दीगौड़ा से हारने के बाद भी वह पिछले पांच साल से पार्टी के लिए काम कर रही हैं। जैसा कि कुछ मीडिया में बताया गया है, किसी ने भी मुझे कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। मैं चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिये जाने की अपनी मांग पर अब भी कायम हूं। वीणा कशप्पनवर का कहना है कि उन्होंने मुझसे ये जरूर कहा कि मेरी मांग पूरी नहीं होगी।

विपक्ष की रैली को भाजपा ने बताया भ्रष्टाचार बचाओ आंदोलन

नईदिल्ली। दिल्ली के रामलीला मैदान में 31 मार्च को विपक्ष की महारैली होने वाली है। इसमें विपक्ष के सभी बड़े नेता के शामिल होने की उम्मीद है। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र बचाओ आंदोलन का नाम दिया है। आप ने कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और शरद पवार जैसे इंडिया गुट के वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक मेगा रैली में शामिल होंगे। आप और कांग्रेस दोनों ही भाजपा शासित केंद्र सरकार की कथित प्रतिशोध की राजनीति के खिलाफ लोकप्रिय गुस्से को आगे बढ़ाने का दावा करते हुए रैली को बड़ी सफलता बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा के शहजाद पूनावाला ने कहा कि ये रैली क्या है? यह और कुछ नहीं बल्कि भ्रष्टाचार बचाओ आंदोलन है जिसका नारा हो सकता है करेंगे हम भ्रष्टाचार, कहेंगे इसको शिष्टाचार, जब होगी जांच, हम चिल्लाएंगे अत्याचार, अत्याचार। उन्होंने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल कहते थे कि वह लालू यादव, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जेल में डालेंगे क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है और आज जब केजरीवाल जेल में हैं, अदालतें उन्हें राहत नहीं दे रही हैं तो वह उसी लालू का सहारा ले रहे हैं प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और कह रहे हैं कि आपने मुझे जेल में क्यों डाला है। तो, यह अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक रूपांतरण है-स्वराज से शराब तक, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से भ्रष्टाचार के औचित्य तक।

मोदी आज मेरठ से करेंगे चुनावी शंखनाद

मेरठ, बागपत, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और कैराना लोकसभा सीट पर फोकस

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के बाद उत्तर प्रदेश के मेरठ में रविवार को एक रैली संबोधित कर राज्य में चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक पदाधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि प्रधानमंत्री की इस रैली में मेरठ के अलावा बागपत, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और कैराना लोकसभा क्षेत्रों के लोग भी शामिल होंगे। भाजपा मुख्यालय से प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता को प्रधानमंत्री की रैली के समन्वय की जिम्मेदारी दी गयी है। चुनाव प्रबंधन में पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं विधान परिषद सदस्य गोविंद नारायण शुक्ला ने बताया, '' प्रधानमंत्री की मेरठ रैली पश्चिमी उप्र में मील का पत्थर साबित होगी।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) इस बार राज्य की सभी 80 सीट पर जीत हासिल करेगा।'' उत्तर प्रदेश में 80 सीट पर सभी सात चरणों में चुनाव होने हैं जिसकी शुरुआत पश्चिमी उप्र से हो रही है। पहले चरण के तहत बिजनौर, मुजफ्फरनगर और कैराना लोकसभा क्षेत्रों में 19 अप्रैल को मतदान होगा। हालांकि मेरठ और बागपत में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा।

मेरठ से भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष अंकित चौधरी ने कहा, '' यह 2024 के चुनाव की पहली रैली है। कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री क्रांति धरा मेरठ से चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं।'' मेरठ के एक अधिकारी ने बताया कि मेरठ में 31 मार्च को प्रधानमंत्री की प्रस्तावित रैली के मद्देनजर सुरक्षा के लिए जिलाधिकारी दीपक मीणा ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत रैली स्थल के आठ किमी के दायरे में हवाई प्रदर्शन, ड्रोन, पतंग या गुब्बारे उड़ाना प्रतिबंधित कर दिया है।

जिलाधिकारी ने सभी थानाध्यक्षों को आदेश दिए हैं कि वह अपने क्षेत्रों में आदेशों का सख्ती से पालन कराएं। मेरठ में भाजपा ने इस बार रामानंद सागर कृत धारावाहिक 'रामायण' में राम की भूमिका निभाने के बाद विख्यात हुए अभिनेता अरुण गोविल को अपना

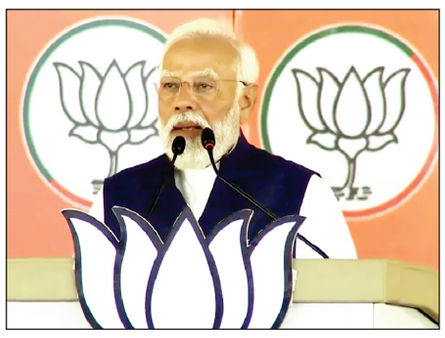

उम्मीदवार बनाया है।

एक राजनीतिक जानकार ने बताया, '' अयोध्या में भगवान श्रीरामलला की मूर्ति इसी वर्ष 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद मोदी राज्य में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत भी अरुण गोविल के क्षेत्र से कर रहे हैं, जो राम की भूमिका निभाने के बाद पूरे देश में आदर के साथ पहचाने जाते हैं।''

अरुण गोविल भी प्रधानमंत्री के मंच पर मौजूद रह सकते हैं। जाट बहुल पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) का प्रभाव है और अभी हाल ही में रालोद भाजपा नीत राजग में शामिल हो गया। भाजपा और रालोद ने मोदी की रैली के लिए व्यापक तैयारी की है। भाजपा की जिला इकाई के प्रमुख शिवकुमार राणा ने बताया कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के मैदान पर रविवार शाम साढ़े तीन बजे होने वाली प्रधानमंत्री की रैली में बसों, कारों और ट्रैक्टर के जरिए भारी भीड़ जुटने की संभावना है।

भाजपा के सहयोगी रालोद के प्रवक्ता आतिर रिजवी ने बताया कि रालोद मुखिया चौधरी जयंत सिंह भाजपा के साथ मंच साझा करेंगे। भाजपा तथा रालोद नेताओं के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी की रैली में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न, गन्ना किसान से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास पर चर्चा होगी। केंद्र सरकार ने शनिवार को चौधरी चरण सिंह को 'भारत रत्न' प्रदान किया है। चौधरी चरण सिंह रालोद प्रमुख जयंत के पितामह और रालोद संस्थापक दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजित सिंह के पिता थे।

खेल
प्रमुख समाचार

चेन्नई के खिलाफ दिल्ली का मुकाबला आज

नईदिल्ली। दिल्ली कैपिटल्स को रविवार को यहां गत चैम्पियन चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के खिलाफ होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच में अपने बल्लेबाजी क्रम में फेरबदल करके विस्फोटक पृथ्वी पृथ्वी शॉ को शामिल करने की जरूरत होगी। मैच शाम सात बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा।

टी20 प्रारूप में हालांकि काफी कुछ टॉस पर निर्भर करता है लेकिन दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) पिछली चार भिड़ंत में सीएसके की चुनौती से पार नहीं पा सकी है और इसमें भी उसकी हार का अंतर 91 रन, 27 रन और 77 रन रहा है जो उसकी हालत दर्शाने के लिए काफी है। और यह भी देखना होगा कि इन तीन करारी शिकस्त में डीसी की कोर टीम लगभग समान ही रही है, बस पिछली भिड़ंत में ऋषभ पंत उपलब्ध नहीं थे। इसे देखते हुए सीएसके के खिलाफ दिल्ली की जीत को टूर्नामेंट का बड़ा उलटफेर भी माना जायेगा। सीएसके एक बार फिर हर विभाग में मजबूत दिख रही है जो कोच रिकी पोंटिंग की डीसी से बिलकुल ही उलट है क्योंकि दिल्ली की टीम अभी तक खेल के दोनों विभाग में कमजोर रही है। सीएसके ने 'अनकैप्ड' समीर रिज्वी को 8.40 करोड़ रुपये में खरीदा और पहली ही आईपील पारी में पंजाब किंग्स के खिलाफ उनके द्वारा जड़े गये दो छक्कों ने दिखा दिया कि फ्रेंचाइजी उन्हें टीम में शामिल करने के लिए इतनी बेताब क्यों थी। सभी फ्रेंचाइजी में डीसी के पास सबसे कमजोर 'टैलेंड स्काउट प्रोग्राम' है जिसका उसे खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हाल में समाप्त हुए रणजी ट्राफी सत्र में 902 रन जुटाकर सबसे ज्यादा रन जुटाने वाले रिकी भुई ने टीम के पिछले मैच में जितना खराब प्रदर्शन किया, उससे घरेलू क्रिकेट और आईपीएल के बीच का अंतर साफ दिखायी दिया। डेविड वॉर्नर भी अब पुरानी फॉर्म में नहीं दिखते जबकि कप्तान पंत को लय में आने में कुछ समय लगेगा।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

तीन बैंकों ने किए क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव

नईदिल्ली। वित्त वर्ष 24 करीब-करीब समाप्त होने को है। नया वित्त वर्ष यानी फाइनैंशियल ईयर 25 शुरू होने में महज एक दिन बचे हुए हैं। ऐसे में नए फाइनैंशियल ईयर से कई योजनाओं, फंडों, मार्केट के नियमों आदि में बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन इसी बीच एक बड़ा बदलाव क्रेडिट कार्ड को लेकर है। भारत के कई बैंक क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव करने जा रहे हैं मगर आईसीआईसीआई, येस बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कार्ड को लेकर नया नियम 1 अप्रैल 2024 से ही लागू करने जा रहे हैं। इन तीनों बैंकों के क्रेडिट कार्ड नियमों में जो बदलाव होने जा रहा है वह रिवॉर्ड पॉइंड और लाउंड एक्सेस बेनिफिट्स से जुड़ा हुआ है।

अंतरिक्ष में भारत जो कर रहा वो हैरान करने वाला : ईएसए

पेरिस। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) के महानिदेशक जोसफ ऐशबैकर ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की तारीफ की। उन्होंने हाल ही में सफल प्रक्षेपणों के लिए इसरो को सराहा। ऐशबैकर ने कहा कि अंतरिक्ष और विशेष रूप से चंद्रमा पर भारत को मिली उपलब्धियां हैरान करने वाली हैं। बता दें, पेरिस में ईएसए की 323वीं परिषद की बैठक हुई थी। इसकी मेजबानी करने के बाद ऐशबैकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर इसरो की प्रशंसा की। इस बैठक में इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने भी भाग लिया था। जोसफ ऐशबैकर ने कहा, भारत अंतरिक्ष में जो हासिल कर रहा है, खासकर चंद्रमा के क्षेत्र में, वह हैरान करने वाला है। हमने आज ईएसए परिषद में इसरो के अध्यक्ष डॉ. एस. सोमनाथ की मेजबानी की।

सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर ताजा आंकड़े जारी किए गए हैं। इन आंकड़ों के अनुसार भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार पांचवे सप्ताह शानदार बढ़ोतरी देखने को मिली है। 22 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 642.631 बिलियन डॉलर पहुंच गया है। यह अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पांचवे सप्ताह के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा कोष में 140 मिलियन डॉलर की वृद्धि देखने को मिली है। यह जानकारी शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई। इससे पहले विदेशी मुद्रा भंडार का सर्वोच्च स्तर 2021 में देखा गया था। उस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार 642.453 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था। आरबीआई का कहना है कि 22 मार्च को समाप्त सप्ताह के दौरान सोने का भंडार 347 मिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ा है।

नई बीमा पॉलिसी एक अप्रैल से सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में

नई दिल्ली। अगर आप 1 अप्रैल 2024 के बाद बीमा खरीदने वाले हैं, तो अब यह आपको सिर्फ डिजटल फॉर्मेट में ही मिलेगा। क्योंकि अब बीमा कंपनी भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के पॉलिसीधारकों के हितों के संरक्षण नियमों के अनुसार पॉलिसी सिर्फ डिजिटल रूप में जारी करेगी। नए नियमों के मुताबिक, बीमा कंपनियों के लिए डीमैट फॉर्म में पॉलिसी जारी करना अनिवार्य है और अब इसे चार बीमा रिपोजिटरी - CAMS रिपोजिटरी, कार्वी, NSDL डेटाबेस मैनेजमेंट और सेंट्रल इंश्योरेंस रिपोजिटरी ऑफ इंडिया द्वारा सुगम बनाया जाएगा। 1 अप्रैल से बीमा कंपनियों के लिए सिर्फ डिजिटल पॉलिसी जारी करना अनिवार्य है। IRDAI के नियमों में कहा गया है, चाहे प्रपोजल इलेक्ट्रॉनिक रूप में मिला हो या किसी और तरीके से, हर बीमाकर्ता सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक रूप में बीमा पॉलिसी जारी करेगा।

ऋण आधारित पूंजी के बिना नहीं बनेगी बात

आकाश प्रकाश

सभी लोग भारत की आर्थिक विकास की यात्रा की खुशी मना रहे हैं। देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर अब 8 प्रतिशत पार कर गई है, जो कम नहीं मानी जा सकती। अधिकांश निवेशक इस धारणा के साथ निवेश कर रहे हैं कि आने वाले दशक में भारत पूरे दस वर्षों की अवधि में वास्तविक जीडीपी में 6.5-8.0 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त कर लेगा।आर्थिक वृद्धि को लेकर जताए जा रहे अनुमान एवं वित्तीय स्थिरता के दावों के दम पर भारत का मूल्यांकन गुणक देश के अब तक के इतिहास के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है। वृद्धि की यह रफ्तार रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित करने और भारत में आंतरिक ऋण से जुड़े हिसाब-किताब को सहज बनाने के लिए जरूरी है।

बाजार के लिए भी यह आवश्यक है क्योंकि यह रफ्तार 11-13 प्रतिशत नॉमिनल जीडीपी वृद्धि की तरफ इशारा करती है। नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर को कंपनियों की आय बढ़ने के एक ठोस संकेत के तौर पर देखा जाता रहा है।

भारत की आर्थिक विकास गाथा की जब चर्चा होती है तो एक मात्र कमजोर पक्ष निजी पूंजी व्यय या पूंजीगत व्यय के रूप में दिखती है। सरकार ने सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के उपाय कर सराहनीय काम किया है परंतु निजी क्षेत्र से बड़े स्तर पर निवेश अब तक आता दिखाई नहीं नहीं हो रहा है। लोकप्रिय धारणा यह है कि निजी क्षेत्र से पूंजीगत व्यय में जब तक तेजी नहीं आएगी तब तक भारत की विकास गाथा अधिक समय तक लोगों की जुबान पर नहीं टिक सकती।

आइए, पहले कुछ आंकड़ों पर विचार करते हैं। जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार ने सत्ता संभाली थी तो सार्वजनिक

निवेश लगभग 2.3 लाख करोड़ रुपये था। मोदी के पहले कार्यकाल में यह आंकड़ा मामूली बढ़कर 3.2 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। दूसरे कार्यकाल में यह आंकड़ा बढ़ता ही गया और लगभग 3.2 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 11 लाख करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2025) पहुंच गया। उदाहरण के लिए रेलवे में सार्वजनिक निवेश पर विचार किया जा सकता है। पिछले 10 वर्षों के दौरान इसका पूंजीगत व्यय 16 गुना बढ़कर 15,000 करोड़ रुपये से 2.5 लाख करोड़ रुपये हो गया है। सड़कों के मामले में भी यही रुझान देखा जा रहा है। सड़क खंड में पूंजी निवेश 9 गुना बढ़कर 3 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया है।

सकल नियत पूंजी निर्माण एक बार फिर 30 प्रतिशत का आंकड़ा पार कर गया है, जो कम होकर 27 प्रतिशत रह गया था। यह आंकड़ा 32-33 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य साधा जा रहा है। ये सभी उत्साह बढ़ाने वाले आंकड़े हैं और सरकार की आकांक्षा और क्रियान्वयन क्षमता में स्वागतयोग्य बदलाव को दर्शाते हैं। यह स्थिति जारी रहनी चाहिए और आशा की जाती है कि यह निरंतरता जारी रहेगी। पूंजीगत व्यय के मामले में निजी क्षेत्र की भूमिका पर सभी की चिंता का कारण यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र से निवेश की एक सीमा है। हम इस बात की उम्मीद नहीं कर सकते कि सार्वजनिक निवेश उसी रफ्तार से बढ़ेगा जितनी रफ्तार से यह पिछले कुछ वर्षों के दौरान बढ़ा है। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि सरकार ने वित्त वर्ष 2026 तक राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.5 प्रतिशत से नीचे रखने और आगे चलकर इसे और कम करने का लक्ष्य तय कर रखा है। ऐसे में सार्वजनिक निवेश में सालाना 10-15 प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना सीमित लग रही है। इसके अलावा रकम खर्च होने से जुड़ा विषय भी है। मुझे नहीं लगता कि रेलवे में लगातार पूंजी व्यय क्रियान्वयन के स्तर पर भी उतना ही कारगर हुआ होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो जितना व्यय हो रहा है वह पूरी तरह इस्तेमाल में आ रहा है या नहीं यह भी देखना होगा। प्रभावी रूप से 2.5 लाख करोड़ रुपये खर्च करना भी सरल नहीं है। कुछ लोगों को निजी क्षेत्र के आगे आने को लेकर अंदेशा है मगर इस बात के पूरे संकेत हैं कि वे भी सार्वजनिक क्षेत्र के साथ मिलकर चलेंगे। पिछले छह महीनों के दौरान मुझे एक भी कंपनी ऐसी नहीं दिखी जहां क्षमता नहीं बढ़ाई गई हो।

फुरसत अगर मिले तो, मुझे पढना जरुर... मै तेरी उलझनों का, मुकम्मल जवाब हूँ.....

हाईकोर्ट ने अरविन्द केजरी वाल (ईडी की कस्टडी) को सीएम पद से हटाने की याचिका को खारिज कर दिया है,इसे राजनीतिक मसला करार दिया है,लोस चुनाव के चलते उप राज्य पाल कोई वैधानिक निर्णय लेंगे ऐसा लगता नहीं है, तो क्या हिरासत से ही केजरी वाल दिल्ली की सरकार चलाएंगे ऐसा लगता है हैदर दिल्ली के सीएम अरविन्द केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी के बाद अब तो अमेरिका की प्रतिक्रिया आई है उसमे कहा गया है कि निष्पक्ष,पारदर्शी हो न्याय। शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम केजरी वाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका ने कड़ा ऐतराज़ जताया है,अमेरिका का कहना है कि वह भारत के इस प्रमुख विपक्षी नेता केजरीवाल की गिरफ्तारी पर नजर रखे हुए है...! अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि हम भारत इस विपक्षी नेता की गिरफ्तारी की रिपोर्ट्स पर नजर बनाए हुए हैं देश में निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया की उम्मीद करते हैं दरअसल केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी के बयान के बाद भारत ने जर्मनी के राजदूत को तलब कर नाराजगी जताई थी।

इस घटनाक्रम के बाद ही अमेरिका की इस मामले पर प्रतिक्रिया आई है,कहीं केजरीवाल को हैवी नेता बनाने वैश्विक साजिश तो नहीं है..?अगर ऐसा नहीं है,तो क्या हेमंत सोरेन किसी राज्य के सीएम नहीं थे? वोभी तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में धरे गए हैं जर्मनी,अमेरिका ने तब क्यों नहीं आवाज उठाई? लालू यादव भी तो बिहार के सीएम थे, उनको जेल में यातना दी गई,झार खंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा भी तो जेल गए थे, आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में ही जेल गए थे ? झारखंड के पूर्वसीएम शीबू सोरेन,हेमंत सोरेन के पिता भी तो जेल गए थे? ओम प्रकाश चौटाला भी जेलगये जयललिता, तमिलनाडु की पूर्व सीएम भी जेलगयी तब क्या हुआ था इन देशों को?

कांग्रेस 3,भाजपा की 2 महिला लोस प्रत्याशी...

महिलाओं के 33% आरक्षण का बिल पास कराने वाली मोदी सरकार ने छग में कुल 11लोस सीटों में 2 महिलाओं को टिकट दी है कांग्रेस ने 3 महिलाओं को चुनाव समर में उतरा है। कांग्रेस की प्रत्याशियों को तो राजनीति विरासत में मिली है, रायगढ़ लोकसभा से

कांग्रेस ने डॉ मेनका देवी सिंह को प्रत्याशी बनाया है, सारंगढ़ रियासत की मेनका एक मजबूत उम्मीदवार हैं। उनके पिता सारंगढ़ के राजा नरेश चन्द्र सिंह 1952 के पहले चुनाव में विधायक बने थे इसके बाद भी तीन बार विधायक बने,इस बीच वे 13 दिनों के लिये मप्र के सीएम भी रहे। इसके बाद उनकी बेटियाँ कमलादेवी रजनीगंधा, पुष्पादेवी भी राजनीति में आई, पुष्पा देवी, लोकसभा सदस्य भी रहीं।

सरगुजा लोस से कांग्रेस ने शशि सिंह को प्रत्याशी बनाया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ी शशि, जिला पंचायत सदस्य भारी मतों से बनी हैं ,पूर्व मंत्री तुलेश्वर सिंह की यह बेटी तेज तर्रार नेत्री हैं। ये राहुल गाँधी की पहले चरण की पदयात्रा में सहयात्री के रूप में पूरे समय शामिल रहीं थीं। कोरबा से कांग्रेस ने ज्योत्सना महंत को चुनाव समर में उतरा है,पिछले लोस चुनाव में मोदी की आंधी में भी ये विजयी रहीं थीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉ चरणदास महंत की पत्नी हैं। भाजपा ने तो कोरबा से सरोज पांडे को प्रत्याशी बनाया है,वैसे उनके लिये ये क्षेत्र नया है, ये मूलतः दुर्ग की रहनेवाली हैं,महासमुंद लोस से भाजपा ने रूप कुमारी चौधरी को प्रत्याशी बनाया है,वे पहले बसना से विधायक, संसदीय सचिव भी रह चुकी हैं।

विधानसभा उपचुनाव भी होना तय ....?

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता,पूर्व सीएम,पाटन के विधायक भूपेश बघेल राजनांदगांव से लोसउम्मीद वार हैं तो बस्तर लोकसभा से कांग्रेस के आदिवासी नेता पूर्व मंत्री विधायक कवासी लखमा चुनाव समर में हैं,बिलासपुर लोसचुनाव से भिलाई के कांग्रेसी विधायक देवेंद्र यादव भी प्रत्याशी बनाये गये हैं तो भाजपा के 9 बार के विधायक,छग सरकार के मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भी रायपुर लोकसभा से चुनाव समर में उतरे हैं, जाहिर हैं इनमें से कुछ के जीतने से विधानसभा सीट रिक्त होगी और 6 माह के भीतर उप चुनाव तय हैं।

दो आईएएस डोमन और गौरव का रिकार्ड.....

छग की राजधानी रायपुर के कलेक्टर गौरव सिंह सिर्फ 2 महीने में मुंगेली तो 3 महीने में बालोद की कलेक्टरी से हटा दिये गये थे,हाँ,सूरजपुर में जरुर वे एक साल तक कलेक्टरी करने में सफल रहे।2013 बैच के आईएएस गौरव सिंह का 3 जिले में 17 महीने कलेक्टरी करने का रिकार्ड दर्ज हो चुका है।एक कलेक्टर ने एक बच्चे से मारपीट करने पर तब के सीएम भूपेश बघेल ने उन्हें तत्काल हटाकर गौरवसिंह को सूरजपुर में पहली बार कलेक्टर बनाया था। इधर प्रमोटी आईएएस डोमन सिंह को मुंगेली,कोरिया, कांकेर, पेंड्रारोड गौरेला, महासमुंद, बलौदाबाजार, राजनांदगांव का कलेक्टर बनकर रिकार्ड बना चुके हैं। एक छत्तीसगढ़िया प्रमोटी आईएएस की इस उपलब्धि

कईयों के लिए ईर्ष्या का कारण भी बन सकता हैवैर छग में नई सरकार बनने के बाद 2009 बैच के आईए एस डोमन सिंह, बिलासपुर में डिप्टी कमिश्नर के पद पर कार्यरत हैं। वैसे अभी तक छग राज्य बनने के बाद 4 जिलों मेंकलेक्टर बनने का रिकॉर्ड सुबोध सिंह, ठा.राम सिंह, सिद्धार्थ कोमल परदेशी सोनमणि वोरा, पी दयानन्द भीम सिंह, एकमात्र महिला आईएएस किरण कौशल के नाम दर्ज है। राम सिंह प्रमोटी आईएएस होने के साथ रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ तथा दुर्ग जैसे बड़े जिले में सफल कलेक्टरी करने का रिकॉर्ड बना चुके हैं।

और अब बस..

- कांग्रेस ने करो या मरो की तर्ज पर तजुर्बेकार,दमदार प्रत्याशियों को मैदान में उतरा है।
- भाजपा के देश के बड़े स्टार प्रचारकों की सूची में छग से केवल सीएम विष्णु देव साय ही शामिल हैं।
- पूर्व सीएम भूपेश के इर्दगिर्द की जगह मतपर्टी से चुनाव कराने के फार्मूले की भी चर्चा तेज है।

विजय संकल्प अभियान के तहत भाजपा ने लगाया हर घर भाजपा का झंडाः कश्यप

विजय संकल्प अभियान से भारत हो गया भगवामय, कार्यकर्ताओं के साथ घरों-घर लगाया भाजपा का झंडा-केदार

रायपुर। वन मंत्री केदार कश्यप लगातार लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए बस्तर के गांवों में जनसंपर्क कर रहे है। शनिवार को मंत्री कश्यप बूथ विजय संकल्प अभियान के तहत कई गांवों में लोगों से संपर्क किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की साय सरकार के विकास कार्यों की जानकारी क्षेत्र के लोगों को प्रदान की।

इसके साथ ही वन मंत्री केदार कशप ने भानपुरी मंडल के तहत बूथ क्रमांक 240-करन्दोला, 247- चपका, 249- मुंजला, 251-देवड़ा और बूथ क्रमांक 263 सोनारपाल में देवड़ल्य कार्यकर्ताओं के घरों में भाजपा का झंडा लगाया।

वनमंत्री केदार कश्यप ने कहा कि बूथ विजय संकल्प अभियान के तहत भाजपा के कार्यकर्ता घरों घर पहुँच रहे हैं। आज बूथ स्तर पर घर-घर जा कर सभी कार्यकर्ताओं ने भाजपा का झंडा लगाया है। पूरा देश भगवामय हो गया है। जबकि कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के लिये नेता बहुत दूर की बात है आज कांग्रेस का झंडा उठाने के लिए उनके पास कार्यकर्ता नही है।

भारत के नवनिर्माण में कार्यकर्ताओं का अहम योगदान- मंत्री केदार कश्यप ने कार्यकर्ताओं से कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए इस बार फिर से मोदी की सरकार बनानी है। बस्तर से महेश कश्यप को भारी मतों से जिताना है। इसके लिए सभी कार्यकर्ता जुट जाए।

वन मंत्री ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि कार्यकर्ता ही भाजपा की ताकत है। सभी विकसित राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे।

भाजपा चुनाव प्रभारी नबीन का 4 तक तूफानी दौरा कार्यक्रम

लोकसभा चुनाव की बनाएंगे रणनीति, प्रत्याशियों की नामांकन रैलियों में होंगे शामिल

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी और बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री नितिन नबीन आगामी 4 अप्रैल तक छत्तीसगढ़ के लोकसभा क्षेत्रों के दौरे पर रहेंगे। शनिवार 30 मार्च को राजधानी पहुँचेंगे। लोकसभा क्षेत्रों का प्रवास करके श्री नबीन लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। भाजपा प्रदेश चुनाव प्रभारी नबीन 30 मार्च को शाम रायपुर पहुँच रहे हैं। यहाँ पहुँचने के बाद कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में बूथ विजय अभियान समिति, विशेष सम्पर्क (सामाजिक टोली), विशेष सम्पर्क (व्यावसायिक टोली), विधायक प्रवास, लाभार्थी सम्पर्क अभियान आदि विषयों पर चर्चा करेंगे। रात्रि 7 बजे से 8 बजे तक महामंत्री एवं संभाग प्रभारी के साथ बैठक करेंगे। रात 9 बजे से 10 बजे तक क्लस्टर प्रभारी, लोकसभा संयोजक, सहसंयोजक व महामंत्री व अपेक्षित पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।

भाजपा प्रदेश चुनाव प्रभारी नबीन 31 मार्च को सुबह साढ़े 10 बजे महासमुंद पहुँचेंगे। यहां दोपहर 12 बजे तक महासमुंद लोकसभा कोर कमेटी, लोकसभा प्रबंध समिति के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद वे महासमुंद जिले के जामगांव में आयोजित महिला सम्मेलन में शामिल होंगे। शाम 5 बजे कांकेर के लिए रवाना होकर साढ़े 7 बजे कांकेर पहुँचेंगे। यहाँ रात 8 बजे से रात साढ़े नौ बजे तक कांकेर लोकसभा कोर कमेटी, लोकसभा प्रबंध समिति की बैठक लेंगे।

भाजपा प्रदेश चुनाव प्रभारी नबीन 1 अप्रैल को नबीन सुबह साढ़े 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक कांकेर, भानुप्रतापपुर, सिहावा, अंतागढ़, केशकाल विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद दोपहर एक बजे धमतरी पहुँचेंगे। दोपहर 2 बजे से 5 शाम बजे तक धमतरी, कुरुद, राजिम, बिंद्रानवागढ़ विधानसभा की बैठक लेंगे। शाम 6 बजे धमतरी से कार द्वारा कुशाभाऊ ठाकरे परिसर, रायपुर पहुँचेंगे। भाजपा प्रदेश चुनाव प्रभारी नबीन 2 अप्रैल को हेलीकॉप्टर द्वारा सुबह 11 बजे कांकेर पहुँचेंगे और भाजपा प्रत्याशी भोजराज नाग की नामांकन रैली में शामिल होंगे। इसके बाद कांकेर से गुरूर के रास्ते कार द्वारा शाम 4 बजे राजनांदगाँव पहुँचेंगे जहां शाम 7 बजे तक डोंगरगढ़, डोंगरगांव, खुज्जी, मानपुर-मोहला विधानसभा की बैठक लेने के बाद वे रात रायपुर पहुँचेंगे। भाजपा प्रदेश चुनाव प्रभारी नबीन 3 अप्रैल को कार द्वारा सुबह 11 बजे महासमुंद पहुँचकर भाजपा प्रत्याशी रूपकुमारी चौधरी की नामांकन रैली में शामिल होंगे। इसके बाद श्री नबीन दोपहर ढाई बजे रवाना होकर शाम 4 बजे दुर्ग पहुँचेंगे और दुर्ग लोकसभा कोर कमेटी, लोकसभा प्रबंध समिति की बैठक लेंगे। इसके बाद 7 बजे दुर्ग, दुर्ग ग्रामीण, वैशाली नगर, भिलाई नगर विधानसभा की बैठक करेंगे।

भाजपा प्रदेश चुनाव प्रभारी नबीन 4 अप्रैल को सुबह साढ़े 10 बजे दुर्ग से कार द्वारा रवाना होकर साढ़े 11 बजे राजनांदगाँव पहुँचेंगे। यहां वे भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडेय की नामांकन रैली में शामिल होंगे।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

कांग्रेस ने जारी किए छग के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची

रायपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 अप्रैल को होने वाले छत्तीसगढ़ के लोकसभा आम चुनाव के पहले चरण के लिए 40 स्टार प्रचार प्रसारकों की सूची शनिवार को जारी की। जिसमें श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी वाडा, सचिन पायलट, श्रीमती रजनी पाटिल, दीपक बैज, डॉ चरण दास महंत, सिद्धारमैया, रेवंत रेड्डी, सुखविंदर सिंह सुख, भूपेश बघेल, टी.एस. सिंहदेव, कुमारी शैलजा, श्रीमती दीपा दासमुंशी, श्रीमती फूलो देवी नेताम, श्रीमती रंजीत रंजन, श्री ताम्रध्वज साहू, श्री धनेन्द्र साहू, श्री मोहन मरकाम, अजय सिंह राहुल, श्रीमती वाई.एस. शर्मिला रेड्डी, राज बब्बर, भक्त चरण दास, इमरान प्रतापगढ़ी, कन्हैया कुमार, अमरजीत भगत, जय सिंह अग्रवाल, गुरु रूद्र कुमार, उमेश पटेल, द्वारिकाधीश यादव, शफी अहमद, सत्यगिरि संकर उलाका, डॉ. चंदन यादव, विजय जांगिड़, श्रीमती अलका लांबा, श्रीनिवास बी.वी., वरुण चौधरी, आकाश शर्मा व नीरज पांडे शामिल है।

19 अप्रैल से 1 जून तक एग्जिट पोल पर रहेगा प्रतिबंध

रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी 19 अप्रैल से 1 जून तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण को प्रतिबंधित किया है। आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण को प्रतिबंधित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में उल्लेखित है कि लोकसभा निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत 19 अप्रैल 2024 को प्रातः 7 बजे से 1 जून 2024 की शाम साढ़े छह बजे तक की अवधि में लोकसभा आम निर्वाचन के संदर्भ में किसी भी तरह के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा। आयोग ने अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन लोकसभा निर्वाचन-2024 अंतर्गत संबंधित लोकसभा क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।

भाजपा प्रत्याशी भोजराज के खिलाफ कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से की शिकायत

रायपुर। कांकेर लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी भोजराज नाग के द्वारा बालोद जिला के डौंडीलोहारा क्षेत्र में चुनावी सभा के दौरान अपने लोकसभा क्षेत्र में तंत्र-मंत्र और नींबू काट कर गांव की जन-समस्याओं को अंधविश्वास के माध्यम से दूर करने का प्रलोभन मतदाताओं को दिये जाने की शिकायत कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त से किया। ज्ञापन में कहा गया है कि वर्तमान समय में सम्पूर्ण भारत में आदर्श आचार संहिता लागू है ऐसे स्थिति में छत्तीसगढ़ के अन्तर्गत कांकेर लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी भोजराज नाग के द्वारा बालोद जिले के डौंडीलोहारा क्षेत्र में चुनावी सभा के दौरान अपने लोकसभा क्षेत्र में तंत्र-मंत्र और नींबू काट कर गांव की जन-समस्याओं को दूर करने का प्रलोभन मतदाताओं को दी जा रही है। इस प्रकार भाजपा प्रत्याशी द्वारा आम मतदाताओं को गुमराह कर अंधविश्वास भरी प्रलोभन दे कर मतदाताओं को छल पूर्वक अपनी ओर प्रभावित करने के उद्देश्य से उक्त अनर्गल वायदे कर वक्तव्य दिये है। जिससे की उक्त वायदे से निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता को दूषित होने की संभावनाओं से इंकार नही किया जा सकता है।

केन्द्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों की बढ़ेगी आय

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर एमएसपी को कानूनी दर्जा मिलेगा। किसान आर्थिक रूप से सक्षम होगा, खुशहाल होगा। बीते 10 वर्ष में मोदी सरकार ने किसानों की आमदनी दोगुनी करने उपज का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने जैसे वादों को पूरा नहीं किया है बल्कि किसानों को कमजोर करने एवं पूंजीपतियों का गुलाम बनाने के लिए तीन काला कृषि कानून लाया जिसका कांग्रेस ने पुरजोर विरोध किया था। भाजपा की नीति में किसान की समृद्धि खुशहाली नहीं है।

किसानों के सुख समृद्धि के लिये 5 गारंटी देती है। कांग्रेस की सरकार बनने पर- एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा। इसके लिए संसद में एक विशेष कानून पारित किया जाएगा। डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले के अनुसार एमएसपी तय की जाएगी। किसानों के ऋण माफ़ करने और आवश्यक ऋण माफ़ी की राशि निर्धारित करने के लिए एक स्थायी कृषि ऋण माफ़ी आयोग की स्थापना की जाएगी। किसानों के फ़सलों के नुक़सान होने पर 30 दिनों के भीतर सीधे बैंक खाते में गारंटीड भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना को फ़िर से डिज़ाइन किया जाएगा। कांग्रेस कृषि उत्पादों के लिए एक आयात-निर्यात नीति बनाएगी और उसे लागू करेगी।

पचास साल बाद फिर मिलेंगे कालीबाड़ी के छात्र

रायपुर। सतता सुंदरी कालीबाड़ी उ. मा. शाला के 1973-74 बैच के छात्र पचास साल बाद सपरिवार रविवार 31 मार्च को एकत्रित होंगे। इस स्वर्ण जयंती मिलन समारोह को यादगार बनाने के लिए विविध कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। तेलीबांधा स्थित एक होटल में सभी सहपाठी दोपहर सपरिवार एकत्रित होंगे। इसी अवसर पर कतिपय गुरूजनों का सम्मानित भी किया जाएगा। समारोह के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया है। इसके पूर्व शनिवार 30 मार्च को सुबह कालीबाड़ी शाला परिसर में सभी छात्रों का फोटो सेशन किया गया। समारोह में सभी छात्र शाला में प्रारंभ में गाई जाने वाली प्रार्थना के साथ सरस्वती पूजा भी करेंगे। सभी अपने-अपने परिचय के साथ अपने परिजनों को भी सबसे परिचित कराएंगे। इसके पश्चात गुरूजनों का सम्मान किया जाएगा। आनंद और उल्लास के क्षणों में मनोरंजक गेम्स के साथ विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखें जाएंगे। समारोह में शामिल होने के लिए विभिन्न शहरों में स्थानांतरित छात्र भी इस दिन विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे।

प्रभारी नितिन नवीन, उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने किया विमोचन

अमित की किताब मोदी मैजिक किताब का राज्य स्तरीय विमोचन

रायपुर। बीजेपी छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी एवं बिहार सरकार में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री नितिन नवीन ने प्रेस वार्ता कर मोदी मैजिक किताब का विमोचन किया और किताब में दिए यूपीए सरकार के 10 वर्ष एवं मोदी सरकार के 10 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों के आंकड़े मीडिया के सामने प्रस्तुत किए,नितिन नवीन ने कहा आंकड़ों से स्पष्ट है मोदी सरकार के 10 वर्षों में कांग्रेस के 55 वर्षों से ज्यादा का काम हुआ है भारत तेज रफ्तार से विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

नवीन ने कहा कांग्रेस का कोई

भी राष्ट्रीय नेता इन आंकड़ों पर चर्चा करने की हिम्मत नही दिखा सकता। नितिन नवीन ने कहा मोदी सरकार गरीबों की सरकार है नितिन ने आंकड़े प्रस्तुत करते हुए बताया कि केवल 10 वर्षों में 2.86 करोड़ बिजली कलेक्शन,4 करोड़ लोगो को आवास,10 करोड़ लोगो को मुफ्त गैस,14 करोड़ लोगो को नल से जल,31 करोड़ से ज्यादा लोगो को 5 लाख का मुफ्त इलाज, 50 करोड़ लोगो को बैंक खाता,81 करोड़ लोगो को मुफ्त राशन मिला है देश ने वाकई विकास की दिशा में एक लंबी छलांग लगाई है और सरकार ने गरीबों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाने का काम किया है। नवीन ने कहा मोदी मैजिक किताब कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगो के लिए एक आइना है इस कार्य के लिए मैं अमित चिमनानी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं।

अरुण साव ने कहा मोदी सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को वर्ष 2014 से 2024 तक कुल 3 लाख 80 हजार करोड़ रूपए दिये गये हैं जबकि कांग्रेस की 2004 से 2014 तक सरकार ने छत्तीसगढ़ को केवल 83 हजार करोड़ रूपए ही दिए।

मोदी सरकार ने 10 वर्षों में छत्तीसगढ़ को लगभग- 52 हजार जीएसटी के मद में, 55 हजार करोड़ कार्पोरेट टैक्स के मद में, 53 हजार करोड़ इंकम टैक्स के मद में, 10 हजार करोड़ कस्टम ड्यूटी के मद में, 5 हजार 2 सौ करोड़ एक्साइज के मद में, 12 हजार 500 करोड़ जीएसटी कंपनशेसन के मद में, वित्त आयोग 2013, 2014, 2015 में 15 हजार करोड़ विभिन्न योजनाओं एवं अन्य मदों में 1 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि दी गई है छत्तीसगढ़ राज्य को मोदी सरकार ने जो मदद दी है वो कांग्रेस से 5 गुना ज्यादा है।

डीजीपी को हाई कोर्ट का नोटिस

रायपुर। न्यायालयीन आदेश की अवहेलना के आरोप से घिरे राज्य के पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा को हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। नाराज कोर्ट ने कहा है कि नोटिस मिलने के बाद तत्काल कोर्ट के समक्ष जवाब पेश किया जाए। स्थानांतरण से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने डीजीपी को नोटिस जारी कर दो महीने के भीतर याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का निराकरण करने का निर्देश दिया था। तय अवधि में निराकरण ना होने पर याचिकाकर्ता ने डीजीपी के खिलाफ न्यायालयीन आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए अवमानना याचिका दायर कर दी है। राजनांदगांव निवासी श्रवण कुमार चौबे सीआइडी रायपुर में निरीक्षक के पद पर पदस्थ हैं। उनके द्वारा गृह जिला-राजनांदगांव में पदस्थ किये जाने हेतु हाई कोर्ट के समक्ष रिट याचिका दायर की थी। याचिका की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा को एक अप्रैल 2006 के स्थानांतरण नीति के तहत दो महीने के भीतर याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का निराकरण करने का निर्देश दिया था। दो महीने से अधिक की अवधि बीत जाने के बाद भी याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर कार्रवाई नहीं की गई। न्यायालयीन आदेश की अवहेलना का आरोप लगाते हुए याचिकाकर्ता ने अपने अधिवक्ता अभिषेक पांडेय व दुर्गा मेहर के माध्यम से डीजीपी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। अवमानना याचिका की सुनवाई जस्टिस रजनी दुबे के सिंगल बेंच में हुई।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्पलेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.